सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com
परिवहन विशेष
वर्ष 02, अंक 222, नई दिल्ली । सोमवार, 21 अक्टूबर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8
देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

हिसाब किताब सिर्फ ऊपर
वाले ने ही सही लगाया,
सबको खाली हाथ भेजा
और खाली हाथ बुलाया…

03 दिवाली से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश
06 क्या 2025 के लिए नीट युजी परीक्षा बदल जाएगा?
08 सीरवी महासभा कर्नाटक होसकोटे जोन 2 के अध्यक्ष ढगलाराम बर्फा

दिल्ली के सदर बाजार में नहीं चलेंगे रिक्शे, जगह-जगह होगी बैरिकेडिंग; पुलिस फोर्स रहेगी तैनात

संजय बाटला

दिल्ली के सदर बाजार में खाली रिक्शा और खाली वाहन का प्रवेश बंद कर दिया गया है। बाजार में जगह-जगह बैरिकेडिंग के साथ ही अर्द्धसैनिक बलों के कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए ड्रोन कैमरों का उपयोग भी किया जाएगा। साथ ही खाली वाहन और रिक्शा का प्रवेश भी सदर बाजार में नहीं होगा।

नई दिल्ली। त्यौहारों के मद्देनजर सदर बाजार में भीड़ और भगदड़ का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस और व्यापारी मामले को संभालने में जुटे हैं। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त (कानून- व्यवस्था) रविंद्र यादव और अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के बाद समस्या के समाधान की कोशिश की गई है।

इसमें पुलिस ने व्यापारियों के साथ मिलकर बाजार का रूट प्लान तैयार किया है। फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश यादव ने बताया कि भीड़ नियंत्रण व सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्पेशल फोर्स तैनात कर दी गई है। आपराधिक व्यक्तियों की निगरानी के लिए 12 टूटी चौक पर विशेष पुलिस वाहन की तैनाती की गई है।

उन्होंने बताया कि सदर बाजार का रोड मैप जारी किया गया है। इसमें पांच जगह पर बैरिकेडिंग पुलिस द्वारा करने पर सहमति बनी है। इसका उद्देश्य है कि अनधिकृत वाहनों का प्रवेश बाजार में न हो। साथ ही वाहन सड़क पर न खड़े हो जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस थाना प्रभारी और बीट ऑफिसर लगातार इस मामले की निगरानी करेंगे।

उन्होंने बताया बाजार में केवल वहीं वाहन जाएगा जो अंदर दुकानदारों का सामान लाया है। दुकानदार भी सड़क पर वाहन ज्यादा देर तक खड़ा नहीं कर सकेंगे। साथ ही कोई भी खाली वाहन व रिक्शा बाजार में प्रवेश नहीं कर पाएगा। केवल बुजुर्ग और महिलाओं को रिक्शा पर अंदर तक बैठकर जाने की इजाजत होगी।

रोड घेर सजाया बाजार, ई-रिक्शा की भी भरमार

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमणकारियों ने पटरियां लगाकर रोड को बाजार बना दिया है। यहां खाने पीने से लेकर कपड़े, जूते, चप्पल, घड़ियां, मोबाइल एक्सेसरीज तक सब कुछ बेचा जा रहा है। अजमेरी गेट की तरफ चल रही इन पटरियों और ई-रिक्शा चालकों के चलते वाहन चालकों को दिनभर परेशानी झेलनी पड़ती है।

अतिक्रमणकारियों की नगर निगम और पुलिस प्रशासन से सांठगांठ के चलते यह लोग जहां इच्छा वहीं पटरी लगाकर सामान बेचने लगते हैं। इन अतिक्रमकारियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर बीच बीच में खानापूर्ति होती है।

पिछले महीने ही नगर निगम ने सख्ती दिखाते हुए छह-सात दिन के लिए इन पटरियों को साफ करा दिया था, उसके बाद फिर से यहां पटरियां सजने लगीं। इसके अलावा नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन या रेलवे स्टेशन के बाहर अवैध तरीके से ई-रिक्शा का स्टैंड बनाया हुआ है और यात्रियों को अपने रिक्शा में बैठाने ही होड़ में चालक आपस में ही झगड़ते रहते हैं।

अवैध तरीके से इन ई-रिक्शा के खड़े होने से रोड पर गाड़ियां फंसी रहती हैं और यातायात पुलिसकर्मी इन रिक्शा चालकों पर कार्रवाई करने के बजाय मूकदर्शक बने रहते हैं। दिन भर जाम की स्थिति बनने रहने से प्रदूषण भी बढ़ रहा है।

महीने का बंधा हुआ है पैसा

अजमेरी गेट की तरफ रेलवे स्टेशन के बाहर पटरी लगाने वाले बताते हैं कि उनका नगर निगम और पुलिस अधिकारियों के लिए महीना बंधा है। उन्होंने बताया कि वह हजार रुपये से लेकर दो हजार रुपये महीना नगर निगम व पुलिस अधिकारियों को देते हैं।

जब कभी सख्ती होती है या कमेटी वाले आते हैं तो पटरियों को हटा दिया जाता है, जिसकी जानकारी उन्हें पहले ही मिल जाती है। कुछ पटरीवालों ने तो यह भी बताया कि पहले उनके पिता यहां पटरी लगाते थे और अब हमने इस काम को संभाल लिया है।

ई-रिक्शा चालकों की दबंगई से लोग परेशान अजमेरी गेट स्थित ओर नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर चार से बाहर निकलते ही सड़क पर ई-रिक्शा की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। लाइन लगाकर इन ई-रिक्शा के खड़ा होने से पैदल चलनेवालों तक के लिए जगह नहीं रहती है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस रोड पर वाहन चालकों का क्या हाल होता होगा। दिनभर यहां वाहन चालक जाम से जूझते रहते हैं।

जब भी निगम अतिक्रमणरोधी अभियान चलाता है, तो स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दे देता है। एक बार अतिक्रमण हट गया है तो अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह पुनः अतिक्रमण न होने दें। हम भी चाहते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो कि देश का बड़ा स्टेशन है उसका बाहरी इलाका स्वच्छ और सुंदर दिखे। -किरण बाला, डिप्टी चेयरमैन, सिटी एसपी जोन

दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए लागू 'ग्रैप' क्या है, जहरीली आबोहवा को रोकने में यह कितना कारगर?

परिवहन विशेष न्यूज

पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, विभिन्न वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत कार्यान्वयन के लिए 'ग्रैप' तैयार किया गया है। ग्रैप को दिल्ली एनसीआर में खराब वायु गुणवत्ता के स्तर के आधार पर चार अलग-अलग चरण में लागू किया जाता है। अभी यहां ग्रैप का पहला चरण लागू है।

नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक होता जा रहा है। प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर में धुंध दिखाई देने लगी है। शनिवार को दिल्ली के अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में एक्यूआई 334 तक पहुंच गया है।

इससे पहले शुक्रवार को राजधानी में सामग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 293 दर्ज किया गया, जिसे 'खराब' श्रेणी जाना जाता है। उधर यमुना नदी में जहरीली झाग दिखाई दी है। कालिंदी कुंज में यमुना नदी के पानी के ऊपर झाग की परत दिख रही है।

राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न भागों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप)-1 के दिशा-निर्देशों के तहत धूल के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया गया। प्रदूषण का स्तर और भी खराब होने की आशंका के चलते ग्रैप-2 की पाबंदियां भी लग सकती हैं।

आइये जानते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति क्या है? इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? दिल्ली में ग्रैप का कौन सा चरण लागू है? क्या होता है ग्रैप? इसमें कब-कौन सी पाबंदियां लागू होती हैं? ग्रैप को लागू कौन करता है?

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति क्या है?

दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दिल्लीवासियों को शनिवार को लगातार छठे दिन 'खराब' वायु गुणवत्ता का सामना करना पड़ा। यहां के कई इलाकों में एक्यूआई 300 के पार चला गया है। शनिवार को अक्षरधाम इलाके में सुबह आठ बजे एक्यूआई गिरकर 334 पर आ गया, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है। इसी समय इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में एक्यूआई 251, आईटीओ में 226 और भीकाजी कामा प्लेस में 273 दर्ज किया गया जो खराब श्रेणी की वायु गुणवत्ता को दर्शाता है।

इससे एक दिन पहले भी प्रदूषण का स्तर दिल्ली के कई इलाकों में 300 के पार दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार (सीपीसीबी), गुरुवार को शहर भर में 13 निगरानी स्टेशनों पर संकेतक 'लाल क्षेत्र' में थे, जबकि एक दिन पहले यह संख्या दो थी। गुरुवार को अशोक विहार, द्वारका सेक्टर 8, पटपड़गंज, पंजाबी बाग, रोहिणी, बवाना, बुराड़ी, जहांगीरपुरी, मुंडका, नरेला, ओखला फेज 2, शादीपुर और विवेक विहार में रीडिंग 300 से ऊपर दर्ज की गई थी।

सीपीसीबी के मुताबिक, जब एक्यूआई 'खराब' श्रेणी में होता है, तो लंबे समय तक संपर्क में रहने पर अधिकांश लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। वहीं 'बहुत खराब' श्रेणी में होने पर लंबे समय तक संपर्क में रहने पर सांस से जुड़ी बीमारी हो सकती है।

प्रदूषण को रोकने के लिए क्या निर्णय लिया गया है?

वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए राजधानी में बीते मंगलवार से ही ग्रैप-1 लागू है। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को ग्रैप-1 के तहत उपायों के सख्त कार्यान्वयन की घोषणा की थी। यह घोषणा दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद हुई, जिसमें पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, धूल नियंत्रण के लिए 99 टीमें निर्माण स्थलों का निरीक्षण करेंगी। पीडब्ल्यूडी 200 एंटी-स्मॉग गन, एमसीडी 30, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) 14 और दिल्ली मेट्रो 80 तैनात करेंगे। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस यातायात प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त कर्मियों को तैनात करेगी और जरूरत पड़ने पर होमगार्ड तैयार रहेंगे।

क्या होता है ग्रैप फार्मूला?

पिछले कुछ वर्षों में देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 2 दिसंबर 2016 में एमसी मेहता बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, विभिन्न वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत कार्यान्वयन के लिए ग्रैप तैयार किया गया है।

ग्रैप को दिल्ली एनसीआर में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के चार अलग-अलग चरण के हिसाब से बांटा गया गया है। ग्रैप का चरण-1 उस वक्त लागू होता है, जब दिल्ली में AQI का स्तर 201-300 के बीच होता है। मौजूदा समय में दिल्ली में ग्रैप का चरण-1 ही प्रभावी है। ग्रैप का दूसरा चरण उस परिस्थिति में प्रभावी होता है, जब राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 301-400 के बीच 'बहुत खराब' मापा जाता है।

चरण III 'गंभीर' वायु गुणवत्ता के बीच लागू किया जाता है। इस वक्त दिल्ली में एक्यूआई 401-450 के बीच होता है। वहीं ग्रैप कार्य योजना का अंतिम और चरण IV 'गंभीर +' वायु गुणवत्ता की परिस्थिति में लागू किया जाता है। चौथे चरण को लागू करने के लिए दिल्ली में AQI स्तर 450 से ज्यादा होना चाहिए। दूसरे और तीसरे चरण की तरह चरण IV के तहत कार्रवाई एक्यूआई के 450 के अनुमानित स्तर तक पहुंचने से कम से कम तीन दिन पहले ही शुरू की जाती है।

ग्रैप को लागू कौन करता है?

ग्रैप पर बनाई गई उप-समिति अग्रिम कार्रवाई की योजना बनाने के लिए समय-समय पर बैठक करती है। इसके साथ है उप-समिति मौजूदा वायु गुणवत्ता और एक्यूआई पूर्वानुमान के आधार पर के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करती है।

उप-समिति ग्रैप के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाइयों की भी समीक्षा करती है। एनसीआर में आने वाले राज्यों और दिल्ली के मुख्य सचिव अक्सर ग्रैप के कार्यों और कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे, खासकर जब हवा की गुणवत्ता गिरती है या 'गंभीर' या 'गंभीर +' श्रेणी में गिरने की आशंका होती है।

अभी दिल्ली में ग्रैप की कौन सी पाबंदियां लागू हैं?

ग्रैप के पहले चरण में खासतौर पर ऐसे उपाय किए जाते हैं, जो सर्दी के मौसम में प्रदूषण रोकने में कारगर हों। इनमें निर्माण स्थलों पर धूल खत्म करने के लिए पानी का छिड़काव, सड़कों की नियमित सफाई, बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों की सख्त जांच, बेहतर यातायात प्रबंधन के साथ ही उद्योग, बिजली संयंत्रों और ईंट-भट्टा, हॉट मिक्स प्लांट से उत्सर्जन को नियंत्रित करना शामिल है। दिल्ली सरकार एक जनवरी तक पटाखे जलाने, रखने और बनाने पर पहले ही रोक लगा चुकी है।

इसके अलावा, पूर्वी और पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे से दिल्ली के लिए ट्रक यातायात के डायवर्जन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू हैं। थर्मल पावर प्लांट में उत्सर्जन मानदंड लागू लिए गए हैं। औद्योगिक और गैर विकास के क्षेत्र में औद्योगिक कचरे का प्रतिदिन उठाव किया जा रहा है। नियमों को नहीं मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी बात कही गई है।

कितना कारगर है ग्रैप?

वायु प्रदूषण के स्तर में अचानक वृद्धि के मुद्दे से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर के लिए ग्रैप तैयार किया गया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, हाल के वर्षों में वायु गुणवत्ता में किए गए कार्यों और सुधार के आधार पर सीपीसीबी ने ग्रैप के तहत सूचीबद्ध कार्यों की व्यापक समीक्षा की थी। सीपीसीबी द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर, संशोधित ग्रैप को एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में लागू किया जाता है। मंत्रालय के अनुसार, 2023 में सभी हितधारकों के निरंतर और ठोस प्रयासों ने पिछले कुछ वर्षों की तुलना में दिल्ली में सामान्य वायु गुणवत्ता मापदंडों को बेहतर बनाने में मदद की है।

दिल्ली में साल-दर-साल प्रदूषण की स्थिति कैसी रही है?

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, पूरे वर्ष 2023 के दौरान दिल्ली का औसत दैनिक एक्यूआई 2018 के बाद से अब तक सबसे अच्छा था। 2020 को छोड़कर 2023 में चार महीने (मार्च, अप्रैल, जून और जुलाई) सबसे अच्छे दैनिक औसत एक्यूआई वाले रहे। वहीं तीन महीने (जनवरी, फरवरी और मई) 2018 से 2023 की पूरी अवधि के दौरान दूसरे सबसे अच्छे दैनिक औसत एक्यूआई के साथ देखे गए।

मासिक दैनिक औसत दिल्ली का एक्यूआई

महीना	2018	2019	2020	2021	2022	2023
जनवरी	328	328	286	324	279	311
फरवरी	243	242	241	288	225	237
मार्च	203	184	128	223	217	170
अप्रैल	222	211	110	202	255	179
मई	217	221	144	144	212	171
जून	202	189	123	147	190	130
जुलाई	104	134	84	110	87	84
अगस्त	111	86	64	107	93	116
सितम्बर	112	98	116	78	104	108
अक्तूबर	269	234	266	173	210	219
नवंबर	335	312	328	377	320	373
दिसंबर	360	337	332	336	319	348

दैनिक औसत पूरे वर्ष के दौरान दिल्ली का एक्यूआई

साल	प्रतिदिन औसत एक्यूआई
2018	225
2019	215
2020	185
2021	209
2022	209
2023	204

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

आनंद विहार की हवा में क्यों घुला जहर? प्रदूषण के हॉटस्पॉट बनने की वजहें आई सामने

आनंद विहार में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बसा यह क्षेत्र अत्यधिक अनियोजित है और यहां बमुश्किल कोई नियमन है। यहां सड़कों के किनारे लगे पेड़ भी सांस लेने के लिए हांफते नजर आते हैं। आसपास के जलस्रोत दम तोड़ चुके हैं। दो बस अड्डे मेट्रो स्टेशन रेलवे स्टेशन होने से लाखों लोगों प्रतिदिन यहां आते जाते हैं।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ने लगा है। दिल्ली के प्रमुख हॉटस्पॉट आनंद विहार में इस अदृश्य खतरे ने डेरा डाल दिया है। यहां की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के बार्डर पर बसा यह क्षेत्र अत्यधिक अनियोजित है और यहां बमुश्किल कोई नियमन है।

यहां सड़कों के किनारे लगे पेड़ भी सांस लेने के लिए हांफते नजर आते हैं। आसपास के जलस्रोत दम तोड़ चुके हैं। दो बस अड्डे, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन होने से लाखों लोगों प्रतिदिन यहां आते जाते हैं। इससे वाहनों का आवागमन भी काफी ज्यादा होता है।

दिल्ली के साथ यहां पड़ोसी गाजियाबाद जिला प्रशासन भी व्यवस्था ठीक करने के लिए एक साथ कभी नहीं जुटते। इसलिए यहां वायु प्रदूषण किसी न किसी कारण से बढ़ा रहता है।

दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट का चल रहा काम

दिल्ली के प्रदूषण हॉटस्पॉट बन चुके आनंद विहार में व्यवस्था का कम अव्यवस्था की स्थिति हर तरफ दिखती है। इस इलाके में कई प्रकार के परिवहन व्यवस्था के कारण रोजाना लाखों लोगों की आवाजाही होती है। यहां दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट का भी काम चल रहा है।

मुख्य सड़क के दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कौशांबी में एक बड़ा बस अड्डा मौजूद है, जहां रोजाना सैकड़ों बसें उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों से यहां पहुंचती हैं। इन यात्रियों की आवाजाही में इस्तेमाल होने वाले अंतरराज्यी बसों की खराब सेहत भी प्रदूषण का बोझ बढ़ा रही हैं।

यहां से गुजरती हैं सैकड़ों डीजल बसें

डीजल चालित सैकड़ों बसें यहां से रोजाना गुजरती हैं। काला धुआं उगलने वाली ये बसें भी प्रदूषण बढ़ाने में अहम कारण साबित होती हैं। प्रदूषण की मात्रा बढ़ाने में दिल्ली में पटपड़गंज व यूपी में साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया की भी भूमिका सवालों के घेरे में हैं। इस इलाके में कई छोटी-छोटी फैक्ट्रियां हैं, जो लगातार धुआं उगलती रहती हैं और वो हवा के रुख के साथ आस-पास फैलती हैं और वायु गुणवत्ता खराब कर रही हैं।

सड़ी हुई अवस्था में हैं इलाके के जलस्रोत

यहां हवा ही नहीं, इलाके के जलस्रोत भी सड़ी हुई अवस्था में हैं, जहां तैरते मलबे से दुर्गंध आ रही है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से निकलने से लकर मुख्य मार्ग (हाईवे) तक पर जहां तहां वाहन खड़े होने से जाम लगा रहता है। यहां से महज पांच किमी की दूरी पर गाजीपूर में कूड़े पहाड़ से निकलती जहरीली गैस इस इलाके की हवा को लगातार दमघोंटू बना रही है। इस स्थिति को देखकर साफ पता चलता है कि यहां वायु प्रदूषण जमीनी स्तर पर चिंता विषय नहीं है।

रविवार को मुख्यमंत्री आतिशी के दौरे से पहले यहां सड़कों पर गंदगी, जहां सड़कों पर अवैध पार्किंग, रेहड़ी-पटरी, सेंट्रल वर्ज से सड़क तक धूल के बीच वाहनों का रेला दिखता था। बीच-बीच में यहां जोर-शोर से सफाई की जाती है, लेकिन यह क्रम कुछ ही दिन चलता है।

दो साल पहले स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट के पर्यावरण विभाग ने डीपीसीसी के लिए किए एक सर्वे में बताया था कि तमाम अव्यवस्थाओं के बीच इस इलाके में वायु प्रदूषण ज्यादा होने का कारण इलाके की सघन बसावट भी है। यहां हवां तेजी से ऊपर की तरफ नहीं निकल पाती है। चूंकि सर्दियों में हवा की गति ज्यादा तेज नहीं रहती है, इससे इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण तुरंत गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है।

आनंद विहार में सप्ताह भर में वायु गुणवत्ता

तारीख	एक्यूआई
14 अक्टूबर	313
15 अक्टूबर	424
16 अक्टूबर	439
17 अक्टूबर	419
18 अक्टूबर	353
19 अक्टूबर	450
20अक्टूबर	454

(सीपीसीबी द्वारा शाम चार बजे जारी आंकड़े)

क्या बोले विशेषज्ञ?

सीएससई के कार्यकारी निदेशक अनुमित राय चौधरी ने कहा कि इस इलाके की मैपिंग करके प्रदूषण के सोर्स पर काम करना होगा। बहुआयामी परिवहन व्यवस्था है साथ में यहीं से हाईवे भी गुजर रहा है, जहां से बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही होती है। अड्डों पर ज्यादा प्रदूषण करने वालों वाहनों को चेक करना होगा। एक चीज की प्लानिंग करनी होगी, तभी इस क्षेत्र में स्थिति बदल सकती है।

सीआरआरआई के परिवहन योजना एवं पर्यावरण प्रभाग के वरिष्ठ विज्ञानी मुक्ति आडवाणी ने कहा कि दिल्ली में वाहनों से होने वाला उत्सर्जन वायु प्रदुषण में बड़ा योगदान देता है। ऐसे में इस इलाके में दो बस अड्डे हैं और यहां ज्यादातर बसें चालू हालत में खड़ी न रहें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है। चालू हालत में खड़ा कोई भी वाहन तीन गुना ज्यादा गैसों का उत्सर्जन करता है। इससे वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ता है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन को निगरानी करनी होगी।

बार-बार हो रही है शरीर में आयरन की कमी, तो जान लें इसके पीछे के कारण

अगर आप भी आयरन रिच फूड्स खाने के बाद भी शरीर में आयरन की कमी रहती है, तो इसके पीछे हो सकते हैं ये कारण। यदि आप ने इन चीजों पर ध्यान न दिया हो तो आयरन रिच फूड्स खाने का कोई फायदा नहीं है।

जब बॉडी में आयरन की कमी होने लगती है, तो आयरन रिच फूड्स और सप्लीमेंट्स का सेवन किया जाता है। अगर फिर भी शरीर में पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं रहता। तो इससे कई समस्याएं बनी रहती हैं। पोषण से भरपूर खाना खाने के बाद भी शरीर में आयरन की कमी महसूस होती है। तो इसके लिए ये 5 कारण जिम्मेदार हो सकता हैं।

आयरन की कमी पूरी ना होने के लिए ये 5 कारण जिम्मेदार हो सकते हैं

एसिड का प्रोडक्शन कम होना

यदि शरीर में लो एसिड प्रोड्यूस होता है यानी एचसीएल का लेवल बॉडी में कम होता है। तो इस वजह से एसिडिटी, एसिड रिफ्लकस जैसी समस्या होती है और पेट में बनने वाली गैस आयरन अब्जॉर्ब होने से रोकती है। इस कारण से सेल्स को पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं मिल पाता है और बॉडी में आयरन की कमी बनी रहती है।

बार-बार इन्फेक्शन होना

किसी भी व्यक्ति को जल्दी-जल्दी इंफेक्शन जैसे यूटीआई या फिर एच पाइलोरी इंफेक्शन जो एक तरह का पेट का इंफेक्शन है। इसके पीछे का कारण शरीर के पैथोजन इम्यूनिटी सिस्टम इंफेक्शन से लड़ने में लग जाता है। इतना ही नहीं, आयरन की मात्रा को अब्जॉर्ब नहीं होने देता। इस कारण आयरन की कमी शरीर में बनी रहती है।

शरीर में सूजन होना

दरअसल, शरीर में सूजन या इंफ्लेमेशन बढ़ जाती हैं, तो सेल्स बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं। वहीं, आयरन अब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। इसकी वजह से आयरन डिफिसिएंसी बनी रहती है।

टैनिन रिच फूड्स

यदि आप टैनिन रिच फूड्स का सेवन करते जैसे कि कॉफी, चाय और चॉकलेट तो शरीर में आयरन की मात्रा नहीं पहुंच पाती है और आयरन की कमी बनी ही रहती है।

विटामिन सी रिच फूड्स की कमी

अगर आपके शरीर में विटामिन सी रिच फूड्स की पर्याप्त मात्रा नहीं होगी, तो आयरन का अब्जॉर्र्शन नहीं होगा।

अंडरआर्म्स के कालेपन से पाएं छुटकारा, इन 5 टिप्स को फॉलो करें

अगर आप अंडरआर्म्स के कालेपन से परेशान हैं तो चिंता छोडिए अब आप इन तरीकों की मदद से अंडरआर्म्स को चमका सकते हैं। स्वस्थ अंडरआर्म्स न केवल आत्मविश्वास की भावना में योगदान करती हैं बल्कि त्वचा की दुर्गंध, जलन और अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं को रोकने में भी मदद करती हैं।

अक्सर जब फैशन की बात आती हैं तो हम सभी महिलाएं स्लीवलेस कपड़े जरुर पहनती हैं। स्लीवलेस कपड़े पहनकर सुंदर तो लगते हैं लेकिन अंडरआर्म्स के कालेपन से हम सभी को शर्मिंदा महसूस होना पड़ता है। लेकिन आप आपको अंडरआर्म्स के कालेपन को दूर करने के लिए बस इन उपायों को फॉलों करना जरुरी है।

सुंदर अंडरआर्म्स न केवल आत्मविश्वास बढ़ाती हैं बल्कि त्वचा की दुर्गंध, जलन और अन्य असुविधाओं की समस्याओं से भी बचाती हैं। विशेष रूप से काले अंडरआर्म्स के कारण लोग अपने पसंदीदा स्लीवलेस कपड़े पहनने में झिझकने लगते हैं। यदि आप अंडरआर्म्स के कालेपन या अस्वस्थता के बारे में चिंतित हैं, तो चिंता न करें, हम आपके लिए लेकर आए ये सरल टिप्स, जिन्हें आप फॉलो कर सकते है।

नियमित रूप से एक्सफोलिएट करें

सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने अंडरआर्म्स के लुक और स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से अपनी अंडरआर्म्स को एक्सफोलिएट करें। ऐसा करने से मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने और इनग्रोन बालों को रोकने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। समय के साथ, काले धब्बे भी कम हो जाएंगे या अपने आप गायब हो जाएंगे। एक्सफोलिएट के लिए आपको बस एक अच्छे बॉडी स्क्रब या चीनी और नारियल तेल जैसे प्राकृतिक चीजों के साथ घर का बना मिश्रण को बना सकते हैं। नहाते समय सप्ताह में 1-2 बार अपनी अंडरआर्म्स को एक्सफोलिएट करें। 1-2 मिनट तक मुलायम गोलाकार गति में धीरे-धीरे मालिश करें और धो लें। एक्सफोलिएट करने के बाद, त्वचा को हाइड्रेट करने के लिए सुखदायक लोशन या एलोवेरा जेल लगाएं।

स्वच्छता जरुरी है

जब पसीना बैक्टीरिया के साथ मिल जाता है तो इससे दुर्गंध और जलन होती है। तो, अंडरआर्म्स को स्वस्थ रखने का सबसे सरल तरीका यह है कि दुर्गंध को रोकने और स्वस्थ त्वचा बनाए रखने के लिए उन्हें पसीने से मुक्त रखा जाए। अंडरआर्म्स को रोजाना पानी और हल्के क्लींजर से धोना चाहिए, खासकर जिम और व्यायाम के बाद।

आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करना

आपके शरीर के बाकी हिस्सों की तरह, अंडरआर्म्स को स्वस्थ रखने के लिए मॉइस्चराइजिंग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह जलन, सूखापन और परतदारपन को रोकने में मदद करता है। हल्के, नॉन-क्लॉगिंग लोशन, एलोवेरा या प्राकृतिक तेल चुनें और नमी को सील करने के लिए अपने अंडरआर्म क्षेत्र को धोने और एक्सफोलिएट करने के बाद उन्हें लगाएं।

नेचुरल डिओडरेंट का यूज करें

बाजार में उपलब्ध डिओडरेंट में कठोर रसायन, अल्कोहल और सुगंध होती है, जो आमतौर पर त्वचा में जलन पैदा करती है और अंडरआर्म्स को भी काला कर देती है। दूसरी ओर, प्राकृतिक डिओडोरेंट हल्के होते हैं और बिना किसी खतरे के गंध से रक्षा करते हैं। अपना स्वयं का घरेलू प्राकृतिक डिओडोरेंट बनाएं जो त्वचा के लिए कोमल और अनुकूल दोनों हो। अंत में, पीएच-संतुलित बॉडी वॉश चुनें और सुगंधित उत्पादों से बचें जो जलन पैदा नहीं करते हैं।

सांस लेने योग्य कपड़े पहनें

क्या आप जानते हैं कि आपके कपड़े भी आपके अंडरआर्म्स को स्वस्थ रखते हैं? गौरतलब है कि सिंथेटिक कपड़े नमी और गर्मी बनाए रखते हैं, जिससे बैक्टीरिया की गतिविधि और जलन को बढ़ावा मिलता है। इसलिए, हमेशा सूती, लिनन और बांस जैसे प्राकृतिक कपड़े चुनें जो त्वचा के छिद्रों को अवरुद्ध न करें। इससे पसीना आना भी कम हो जाता है। इसके अलावा, अपनी त्वचा के करीब बेहतर वायु प्रवाह के लिए ढीले-ढाले कपड़े पहनें।

इसके अलावा, आप नींबू, एलोवेरा, बेकिंग सोडा, सेब साइडर सिरका आदि जैसे कुछ अद्भुत घरेलू उपचार भी आजमा सकते हैं।

गुलाबी ठंड में दक्षिण भारत के इन 5 जगहों को एक्सप्लोर करें, रोमांच से भरपूर होगी यात्रा

सर्दियों के मौसम में अगर आप कहीं घूमने की सोच रहे हैं, तो आप साउथ इंडिया के इन जगहों पर घूमने के लिए जरुर जाएं। इन जगहों पर सुहावना मौसम, सुंदर दृश्य, ठंडी हवा और कई सुंदर चाय बागान देखने को मिलते हैं। आप गुलाबी ठंड में दक्षिण भारत की सुखद एहसास ले सकते हैं।

दिवाली के बाद से सर्दियां लगभग शुरु हो जाती हैं और सर्दी का एहसास भी अब महसूस होने लगा है। इस दौरान घूमने का एक अलग ही मजा होता है। अगर आप भी घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आप साउथ इंडिया के इन जगहों पर जरुर जाएं।

शुरुआती सर्दी के मौसम में कई लोग बर्फ से ढके पहाड़ देखने जरुर जाते हैं। लेकिन आप गुलाबी ठंड में दक्षिण भारत की सुखद एहसास ले सकते हैं। अगर आप सर्दियों की ठंडी हवा से बचना चाहते हैं, तो आप इन जगहों पर घूमने जरुर जाएं।

ऊटी

तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में नीलगिरि पहाड़ियों में स्थित, ऊटी दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यहां सुहावना मौसम, सुंदर दृश्य, ठंडी हवा और कई सुंदर चाय बागान देखने को मिलते हैं। इसके अलावा, प्रकृति के बीच एक टॉय ट्रेन की सवारी उन लोगों के लिए एकदम सही है जो एक आरामदायक छुट्टी की तलाश में हैं। दिल्ली से ऊटी की 4-5 दिन की यात्रा में आपके बजट के आधार पर प्रति व्यक्ति लगभग 35,000 रुपये - 45,000 रुपये का खर्च आ सकता है। ऊटी में इन बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है। सर्कस, कुछ कुछ होता है और गोलमाल अगेन जैसी फिल्मों की शूटिंग ऊटी में हुई थी।

कूर्ग

इस लिस्ट में अगला स्थान कूर्ग का है, जो भारत के स्कॉटलैंड के नाम से मशहूर है। यह समृद्ध संस्कृति, सुंदर दृश्यों, झरनों, रोमांच और आश्चर्यजनक कॉफी बागानों का के लिए जाना जाता है। यहां का मुख्य पर्यटक आकर्षण तमारा कार्निवल, मदिकेरी किला, एबी और इरुप्पु फॉल्स और होन्नमाना केरे झील हैं। कूर्ग की एक राउंड ट्रिप के लिए आपको ऊटी जितना ही खर्च करना पड़ सकता है।

अलेप्पी

अलेप्पी भारत के केरल में सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। वेनिस के रूप में लोकप्रिय यह गंतव्य बैकवाटर, हरे-भरे दृश्य और सुंदर समुद्र तटों का घर है। यह स्थान एक रोमांटिक माहौल प्रदान करता है और यह जगह उन लोगों के लिए आदर्श है जो अपने सहयोगियों के साथ कुछ खास समय बिताना चाहते हैं। यहां के प्रमुख आकर्षण अलाप्पुझा और मरारी बीच, पुन्नमदा झील पर हाउस बोटिंग और कुमारकोम पक्षी अभयारण्य हैं। यहां एक राउंड ट्रिप के लिए आपके पैकेज के अनुसार प्रति व्यक्ति 40,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का खर्च आ सकता है।

वायनाड

इस लिस्ट में अगला स्थान केरल का वायनाड है। हरी-भरी हरियाली, वन्य जीव और धुंध भरा मौसम, यह जगह सर्दियों में घूमने के लिए एकदम बढ़िया है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। यहां के टॉप पर्यटक आकर्षण एडक्कल गुफाएं, चेम्बरा पीक, कुरुवा द्वीप और करापुझा बांध हैं। वायनाड की 3 से 4 दिन की यात्रा का खर्च पैकेज के आधार पर प्रति व्यक्ति 30,000 रुपये से 40,000 रुपये हो सकता है।

कोडईकनाल

तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले की पहाड़ियों के बीच स्थित यह जगह हिल स्टेशन की राजकुमारी के नाम से मशहूर है। ठंड के महीनों के दौरान कपल के घूमने के लिए यह जगह एकदम मस्त है। यहां के कुछ प्रमुख पर्यटक आकर्षण कोडाई और बेरिजम झीलें, ग्रीन वैली, बियर शोला फॉल्स, तलैयार फॉल्स, कुक्कल गुफाएं और अन्य हैं। दिल्ली से यहां आने-जाने का खर्च प्रति व्यक्ति 30,000 रुपये से 40,000 रुपये हो सकता है।

नहीं चला राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी का जादू, मल्लिका शेरावत- विजय राज रोमांटिक कॉमेडी में छाए

बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी अभिनीत फिल्म 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' शुक्रवार को आलिया भट्ट की फिल्म 'जिगरा' से टकरा रही है, सोशल मीडिया यूजर्स ने कॉमेडी फिल्म को एक अच्छी खासी मजेदार फिल्म माना है।

बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी अभिनीत फिल्म 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' शुक्रवार को आलिया भट्ट की फिल्म 'जिगरा' से टकरा रही है, सोशल मीडिया यूजर्स ने कॉमेडी फिल्म को एक अच्छी खासी मजेदार फिल्म माना है। फिल्म में विक्की (राजकुमार) और विद्या (तृप्ति) की एक मजेदार यात्रा दिखाई गई है, जिसमें वे अपने परिवार के साथ मिलकर ऋषिकेश के खूबसूरत शहर में अपनी खोई हुई "सुहागरात सीडी" को वापस पाने की कोशिश करते हैं। मल्लिका शेरावत और परिवार के बाकी सदस्यों की मदद से यह जोड़ा पुलिस और परिवार के बड़ों से अपील करने से लेकर रात में कब्रिस्तान में जाने तक कोई कसर नहीं छोड़ता। आइये जानते हैं इस रोमांटिक कॉमेडी की विस्तृत समीक्षा

कहानी

कहानी ऋषिकेश से शुरू होती है और वर्ष 1997 में सेट की जाती है, जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन नहीं हुआ था। फिल्म में विक्की (राजकुमार राव) नाम का एक लड़का है, जो मेहंदी लगाने वाला कलाकार है। विक्की खुद को किसी सुपरस्टार से कम नहीं मानता है, और उसका सपना एक लेडी डॉक्टर से शादी करना है। उसे विद्या (तृप्ति डिमरी द्वारा अभिनीत) नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, जो एक डॉक्टर है। किसी तरह दोनों की शादी हो जाती है। क्या विक्की को सीडी वापस मिलेगी या नहीं? क्या विद्या को खोई हुई सीडी के बारे में पता चलेगा? विक्की और विद्या (और अन्य) के लिए स्थिति और भी ज़्यादा भयावह हो जाने वाली क्या बात है? जानने के लिए विक्की विद्या का वो वाला वीडियो देखें।

विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के लिए क्या कारगर है

विक्की विद्या का वो वाला वीडियो बेहतरीन कॉमेडी है। संवाद मजाकिया से लेकर बेवकूफी भरे और पूरी तरह से पागल होने तक के हैं और अगर हम इसे देखने जाएं तो यह एक बेहतरीन संयोजन है। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो या तो आपको खूब हंसाता है या फिर आपको 90 और 00 के दशक की कॉमेडी और ड्रामा की याद दिलाता है। फिल्म खुद को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। इसका इरादा साफ है और वह है अपने दर्शकों को पुरानी यादों की सैर पर ले जाना; एक ऐसा समय जब चीजें सरल थीं और एक ऐसा समय जब हम छोटी-छोटी चीजों में खुशी और आनंद ढूंढ़ते थे।

अभिनय

फिल्म की कहानी कई जगहों पर काफी प्रेडिक्टेबल है, जो फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है, लेकिन अगर कलाकारों के अभिनय की बात करें तो यह काफी प्रभावशाली है। कमजोर कहानी के बावजूद, स्टार कास्ट ने फिल्म को एक साथ बांधे रखा है। भले ही फिल्म की कहानी में नयापन न हो, लेकिन राजकुमार, विजय राज और मल्लिका शेरावत का अभिनय लाजवाब है। उनके ज्यादातर डायलॉग्स पर आपको हंसी जरूर आएगी।

दूसरी ओर, तृप्ति डिमरी अपने रोल के मामले में एक बार फिर से फेल होती नजर आ रही हैं। उन्होंने ऐसा रोल चुना है, जिसमें उनके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है; हालांकि, राजकुमार राव के साथ जिन दृश्यों में वे हैं, वे एक जोड़ी के रूप में अच्छे लगते हैं। अश्विनी कालसेकर ने भी फिल्म में कैमियो किया है, जो आपको बहुत पसंद आएगा। टिकू तलसानिया ने राजकुमार राव के दादा की भूमिका निभाई है। अर्चना पूरन सिंह ने तृप्ति डिमरी की मां की भूमिका निभाई है। दोनों दिग्गजों की बेजोड़ एक्टिंग आपको जरूर प्रभावित करेगी। मल्लिका शेरावत ने राजकुमार राव की बड़ी बहन चंदा की भूमिका निभाई है। विजय राज भी अपनी भूमिका से आपको प्रभावित करेंगे और दोनों अपने संवादों से आपको जरूर गुदगुदाएंगे।

90 के दशक के दो गानों के बीच का रोमांस फिल्म में नया फ्लेवर जोड़ता है। निर्देशन राज शांडिल्य ने विक्की विद्या का वो वाला वीडियो निर्देशित किया है। फिल्म सिर्फ रोमांटिक कॉमेडी ही नहीं है, बल्कि इसमें हॉरर फैक्टर भी है, जिसकी उम्मीद इसके ट्रेलर को देखने के बाद नहीं थी। फिल्म कई जगहों पर बिखरी हुई है और थोड़ी बोझिल हो जाती है। कई सीक्वेंस ऐसे हैं जिनके बिना फिल्म पूरी हो सकती थी। कुछ सीन आपको हंसाएंगे लेकिन कहानी से उनका कोई लेना-देना नहीं है। इन सीन को टाला जा सकता था।

विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का अंतिम फैसला

विक्की विद्या का वो वाला वीडियो एक मजेदार, हल्का-फुल्का कॉमेडी-ड्रामा है जो एक अच्छे टाइमपास वॉच की श्रेणी में आता है। यह आपको पुरानी यादें ताज़ा कर देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो 90 के दशक की कॉमेडी देखते हुए बड़े हुए हैं, और यह आपको एक सरल समय में ले जाता है। लंबाई और संपादन में थोड़ी समस्याओं के बावजूद, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो दोस्तों और परिवार के साथ सिनेमाघरों में देखने लायक है। आप अब अपने नज़दीकी थिएटर में विक्की विद्या का वो वाला वीडियो देख सकते हैं।

दिवाली से पहले घर से इन 6 चीजों को निकाल दें, अन्यथा बनीं रहेगी दरिद्रता

दिवाली से पहले घर की साफ-सफाई जरुर की जाती है। शास्त्रों मे बताया गया है जिन घरों में साफ-सफाई की जाती है, वहां मां लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। इस लेख में हम आपको ऐसी वस्तुओं के बारें में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप दिवाली से पहले घर से बाहर निकाल देना चाहिए।

कार्तिक मास की अमावस्या की तिथि पर हर साल दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। इस साल पूरे देश में 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। दिवाली के दिन भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। दिवाली का त्योहार पांच दिनों तक चलता है, इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, दिवाली के दिन माता लक्ष्मी हर घर में भ्रमण करती है। इस दौरान घर की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास साफ और स्वच्छ जगह पर ही होता है। शास्त्रों मे बताया गया है जिन घरों में साफ-सफाई की जाती है, वहां मां लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। ऐसे में दिवाली से पहले घर से बाहर इन चीजों को निकाल दे, वरना माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है।

दिवाली से पहले इन चीजों को घर से बाहर निकाल दें

टूटी-फूटी वस्तुएं

यदि आपके घर में टूटी हुई चीजें, जैसे कि बर्तन, फर्नीचर या सजावटी सामान, नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकता है। इन्हें घर से तुरंत ही निकाल दें।

बिना उपयोग की जाने वाली वस्तुएं

आमतौर पर लोग बिना उपयोग में आने वाली वस्तुओं को भी घर में रखे रहते हैं, हालांकि, वास्तु के अनुसार इन चीजों को घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता है। दिवाली की सफाई के समय इन वस्तुओं को घर से निकाल देना चाहिए। जैसे कि पुराने कपड़े, किताबें या उपकरण आदि।

अशुभ तस्वीरें

ध्यान रहे कि घर में कभी भी नकारात्मकता को दर्शाने वाली तस्वीरों को नहीं लगाना चाहिए। इन्हें घर से हटाकर सकारात्मक और प्रेरणादायक चित्रों को लगाना चाहिए।

सूखे और मृत पौधे

अगर आपके घर में सूखे और मुरझाए हुए पेड़-पौधे को घर से तुरंत निकाल दें क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा लाते है। घर में नए और हरे पौधे लगाने चाहिए। हरे पौधे जीवन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

खराब रिश्ते की यादें

यदि आपके जीवन में किसी बुरे अनुभव या रिश्तों की याद दिलाते हैं। दिवाली की सफाई के दौरान इन चीजों को घर से बाहर निकाल दें। चाहे तो आप इन चीजों को दान कर दें।

सदर बाजार थाने के 11 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, सड़कों और फुटपाथ पर अतिक्रमण को दिया बढ़ावा

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली पुलिस ने सदर बाजार में अवैध रेडी पटरी के मुद्दे पर बड़ी कार्रवाई की है। 11 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। जन सरोकार के तहत इस मुद्दे को उठाया था। फेडरेशन आफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन और कन्फेडरेशन आफ सदर ट्रेडर्स एसोसिएशन (कोस्टा) ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है।

दिल्ली। सदर बाजार में जन सरोकार के तहत दैनिक जागरण द्वारा उठाए गए अवैध रेडी पटरी के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सदर बाजार में तैनात 11 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

शुक्रवार देर शाम कार्रवाई में सभी 11 कॉन्स्टेबल को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। फेडरेशन आफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र शर्मा ने इस कार्रवाई के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि अगर मीडिया जन सरोकारों को उठाए तो कार्रवाई होती है।

जन सरोकार के तहत सोमवार से सदर बाजार में विकराल हुई अतिक्रमण की समस्या तथा उसमें दिल्ली पुलिस की मिलीभगत को प्रमुखता से उठाया था, तथा लगातार चेताया कि किस तरह वहां भगदड़ की स्थिति पैदा हो रही है।

कन्फेडरेशन आफ सदर ट्रेडर्स एसोसिएशन (कोस्टा) के महासचिव देव राज बवेजा ने कहा कि यह मीडिया और दुकानदारों की जागरूकता का असर है।

दिल्ली व्यापार महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र कपूर ने कहा कि सदर बाजार की बिगड़ती स्थिति की खबरें लगातार दैनिक जागरण के माध्यम से शासन और प्रशासन तक पहुंचाई जा रही थीं, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली पुलिस आयुक्त ने विशेष आयुक्त पुलिस (लॉ एंड ऑर्डर), संयुक्त आयुक्त (सेंट्रल रेंज) सहित तीनों डीसीपी और अन्य उच्च अधिकारियों को ग्राउंड ज़ीरो पर स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा।

इस निरीक्षण के बाद, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, सदर बाजार पुलिस स्टेशन के 11 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में कोताही बरतने के चलते तुरंत प्रभाव से लाइन हाज़िर कर दिया गया। कोस्टा और दिल्ली व्यापार महासंघ ने इस त्वरित कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त महोदय और उनकी टीम का धन्यवाद किया है।

महासचिव ने बाजार की स्थिति में सुधार और व्यापारियों के लिए बेहतर सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस आयुक्त से आगे भी सहयोग करने की इच्छा शक्ति की कामना की है व धन्यवाद किया है।

दिल्ली में हुए धमाके का वीडियो आया सामने सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार में आई दरारें

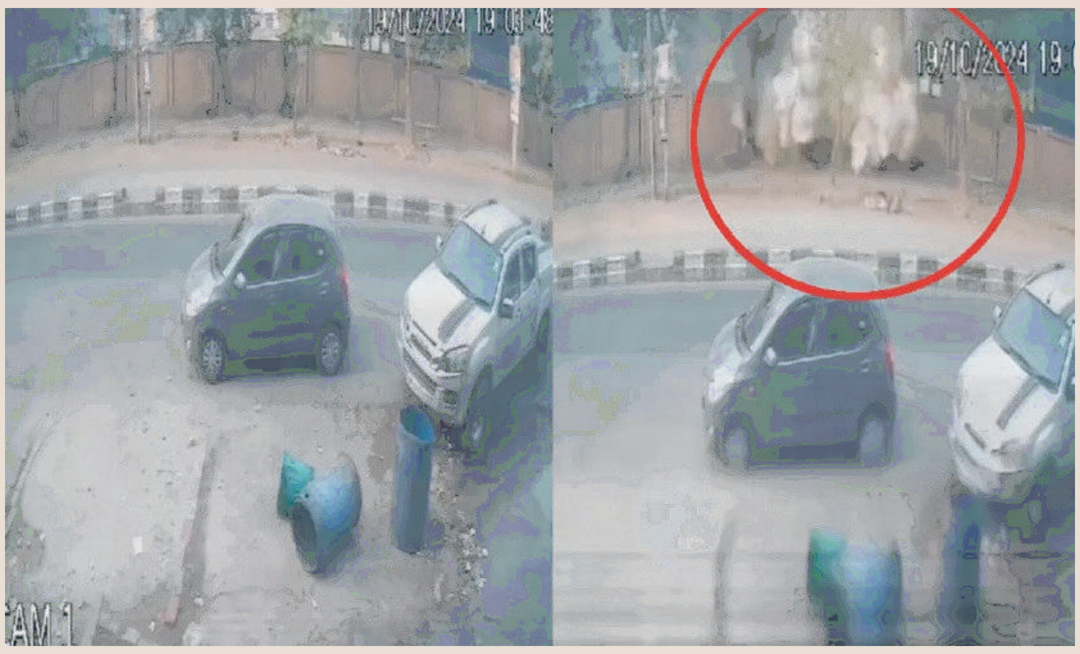

दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। यह धमाका रविवार सुबह सात बजे लगभग हुआ है। धमाका उस समय हुआ है देशभर में त्योहारों का सीजन है। पुलिस आतंकी हमले के एंगल से भी जांच कर रही है। दीवार के पास से सफेद पाउडर भी मिला है। पुलिस पता लगा रही है कि यह कहीं बम ब्लास्ट तो नहीं था।

नई दिल्ली। रोहिणी जिले के प्रशांत विहार में स्थित सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास हुए ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। धमाका रविवार को सुबह साढ़े सात बजे हुआ है। दीवार के पास सफेद पाउडर भी बरामद हुआ है। मामले में दिल्ली पुलिस, एनआईए, एनएसजी सहित केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं।

धमाके में किसी भी तरह का जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि अभी यह पता नहीं लग पाया है कि यह बम बलास्ट तो नहीं था? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। दिवाली से पहले हुए धमाके को आतंकी हमले से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

छह तरह के केमिकल हुए इस्तेमाल

रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि धमाके के कारणों का पता लगाने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया है। दीवार के पास से मिले सफेद पाउडर में अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम का मिक्सचर था। इस धमाके में छह तरह के केमिकल इस्तेमाल हुए हैं। यह क्रूड बम था। टेरर एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता।

एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत मामला दर्ज

प्रशांत विहार पुलिस ने एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि जांच जारी है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रोहिणी ब्लास्ट की रिपोर्ट मांगी है। ब्लास्ट टाइप की जानकारी अभी नहीं मिल सकी है।

एनएसजी की बम डिस्पोजल टीम घटनास्थल के आसपास बहुत ही बारीकी से जांच कर रही है। कई बारीक कण मौके से एकत्र किए। वहीं, एनआईए की टीम भी जांच में जुट गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मामला ट्रांसफर होने की बात कही जा रही है।

20 मिनट तक उठता रहा धुआं

जिस समय धमाका हुआ, 50 मीटर की दूरी पर ही लव पूरी वाली शॉप पर करीब 25 लोग मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, ब्लास्ट होते ही सफेद धुआं करीब 20 मिनट तक उठता रहा।

दमकल की दो गाड़ियां मौके पर भेजी गई। क्रूड बम होने की आशंका जताई जा रही है। रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक का मोबाइल कॉल डेटा भी पुलिस खंगाल रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से जानकारी जुटा रही है।

दिवाली से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश, CRPF स्कूल की दीवार के पास धमाका; कारों और दुकानों के शीशे टूटे

दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-14 में रविवार सुबह सीआरपीएफ स्कूल के पास जोरदार धमाका हुआ। धमाके से आसपास की दुकानों कार्यालयों और गाड़ियों के शीशे टूट गए। स्कूल की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर जांच कर रही हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दीवार के पास मिले सफेद पाउडर की भी जांच चल रही है।

नई दिल्ली। त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली में हाई अलर्ट के बावजूद रविवार सुबह रोहिणी सेक्टर-14 के प्रशांत विहार स्थित सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास जोरदार धमाके ने दिल्ली में दहशत फैला दी। धमाका इतना जोरदार था कि तीन-चार किलोमीटर दूर तक लोगों ने आवाज सुनी और धमाके से निकले सफेद धुएं का गुबार देखा।

करीब 20 मिनट तब आसमान में गुबार फैला रहा। गनीमत रही कि रविवार को छुट्टी का दिन था और धमाका सुबह 7:03 बजे हुआ, तब आसपास लोग मौजूद नहीं थे। घटनास्थल से करीब 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक दुकान के बाहर कई लोग खड़े थे, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ।

दुकानों और कारों के शीशे टूटे

तेज धमाका होने के कारण आसपास की कई दुकानों, कार्यालयों व गाड़ियों के शीशे टूट गए। स्कूल की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई और मौके से काफी देर तक दुर्गंध आ रही थी। धमाका होने के काफी देर बाद सुबह करीब 7.47 बजे पर पुलिस को कॉल मिली।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के अलावा पहले क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, फायर बिग्रेड, डॉग स्क्वॉयड, बम स्क्वॉयड, कैट एंबुलेंस की टीम मौके पर पहुंची।

केंद्रीय एजेंसियों ने केमिकल के लिए सैंपल

धमाके में विस्फोटक का पता चलने पर तमाम केंद्रीय एजेंसियों एनडीआरएफ (NDRF), एनएसजी व एनआईए (NSG & NIA) के अलावा एफएसएल व सीएफएसएल की टीमें भी बुला ली गईं। केंद्रीय एजेंसियों के एक्सपर्ट ने अपने-अपने स्तर पर प्रथम दृष्टया मौके से उठाए गए केमिकल व अन्य नमूने को पास स्थित खाली जगह पर ले जाकर जांच की।

विस्फोटक में कौन से पदार्थ थे शामिल

जांच से ब्लास्ट में फिलहाल नाइट्रेट व क्लोराइड का इस्तेमाल किए जाने का पता चला है, जिसे उच्च श्रेणी विस्फोटक में नहीं माना जाता है। विस्फोटक का पता चलने के बाद प्रशांत विहार थाने में विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।

अगर कहीं मिले तुमसे हरि

अगर कहीं मिले तुमसे हरि,
तो कहना उनसे खरी-खरी।
यहाँ महंगाई सर पर है चढ़ी,
जनता गुस्से में है लाल-पीली!
जीना मुश्किल यहां हर घड़ी।

अगर कहीं मिले तुमसे हरि,
तो कहना उनसे खरी-खरी।
किसको किसी की नहीं पड़ी,
मोबाइल में दुनिया घुसी पड़ी!
दिन का चैन व रात भी ले उड़ी।

अगर कहीं मिले तुमसे हरि,
तो कहना उनसे खरी-खरी।
सरकार है आंखें मूंदे खड़ी,
दंगाइयों की त्योरिया हैं चढ़ी!
अब सबक सिखाने की है घड़ी।

अगर कहीं मिले तुमसे हरि,
तो कहना उनसे खरी-खरी।
वस्त्रों के यहां अंबार लगे हैं,
फिर पापा की यह परियां क्यों?
न्यून वस्त्रों सबके सामने है खड़ी?

संजय एम. तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इंदौर (मध्यप्रदेश)
98260-25986

कॉलेज कर चुके है ईडब्ल्यूएस सीटों के बढ़ने पर अतिरिक्त शिक्षकों के पदों की मांग की

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध विभागों व कॉलेजों में पिछले दो साल से सहायक प्रोफेसर के पदों पर स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। बता दें कि अभी तक कॉलेजों में शिक्षकों के 80 फीसदी पदों को भरा जा चुका है है, यानी 4700 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है लेकिन शिक्षा मंत्रालय ने अभी तक ईडब्ल्यूएस सीटें दिल्ली विश्वविद्यालय के विभागों / कॉलेजों को आबंटित नहीं की है। जबकि शिक्षा मंत्रालय ने पिछले दिनों डूटा को यह आश्वासन दिया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 75 फीसदी पदों पर स्थायी नियुक्ति के बाद ईडब्ल्यूएस सीटें दी जाएंगी लेकिन कई महीने बीत गए शिक्षा मंत्रालय से अभी तक सीटें नहीं मिली है। जबकि कॉलेजों से ईडब्ल्यूएस की सीटें कितनी बढ़ेंगी उसके आंकड़े मंगवा लिए गए। डीयू में ईडब्ल्यूएस कोटे की लगभग 3000 सीटें बनती है। फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस (शिक्षक संगठन) ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर मांग की है कि दिल्ली विश्वविद्यालय को जल्द से जल्द ईडब्ल्यूएस सीटों को आबंटित करें जिससे कि कॉलेजों को ईडब्ल्यूएस सीटों का लाभ मिल सके।

फोरम के अध्यक्ष डॉ हंसराज सुमन बताया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव (कॉलेजिज) ने एक साल पहले विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी कॉलेजों के प्राचार्यो तथा संस्थान के निदेशकों को सर्कुलर जारी करते हुए ईडब्ल्यूएस की 10 फीसदी अतिरिक्त पदों की आवश्यकता के विषय में जानकारी मांगी गई थीं कि 10 फीसदी सीटों के बढ़ने पर उनके कॉलेज में कितने शिक्षक पदों की आवश्यकता है। कॉलेजों से उनके आंकड़े देने को कहा था। कॉलेजों के प्राचार्यों ने शैक्षिक व गैर शैक्षिक पदों के आंकड़े विश्वविद्यालय को भेज दिए। भेजें गए शैक्षिक पदों के आंकड़ों को लेकर पिछले दिनों डूटा के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय भागी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले थे। शिक्षा मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे ही अपने कॉलेजों में शिक्षकों की 75 फीसदी पदों पर स्थायी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेगा शिक्षा मंत्रालय उन्हें ईडब्ल्यूएस के कारण बढ़ी सीटें दे देगा। डॉ.सुमन ने बताया है कि वर्तमान डीयू कॉलेजों में 80 फीसदी सहायक प्रोफेसरों की स्थायी नियुक्ति हो चुकी है तथा स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है बावजूद इसके अभी तक शिक्षा मंत्रालय ने अपना आश्वासन पूरा नहीं किया। उन्होंने बताया है कि शैक्षिक सत्र -2025 --26 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्र चौथे वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे जहाँ शिक्षकों की मांग बढ़ जाएगी। कॉलेजों में अभी तक स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के आधार पर की गई है।

उन्होंने डूटा अध्यक्ष प्रोफेसर ए. के. भागी से एससी/एसटी व ओबीसी कोटे के शिक्षकों का बैकलॉग व शॉर्टफाल पदों पदों की स्थिति पर लंबी मुलाकात कर उनसे ईडब्ल्यूएस की अतिरिक्त सीटों पर भी बातचीत की। प्रोफेसर भागी ने उन्हें बताया है कि ईडब्ल्यूएस की टीचिंग पोस्टों के लिए शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से पुनः जल्द ही मिलने वाले है। प्रोफेसर भागी ने डॉ. सुमन को बताया है कि ईडब्ल्यूएस की टीचिंग पोस्ट के लिए 16 अक्टूबर को डूटा की ओर से शिक्षा मंत्रालय व यूजीसी को पत्र लिखकर मांग की है तथा जल्द ही वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलेंगे। उनका कहना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने पहले विज्ञापित पदों पर 80 फीसदी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। उन्हें जल्द ही शिक्षा मंत्रालय दिल्ली विश्वविद्यालय को 25 फीसदी ईडब्ल्यूएस की अतिरिक्त सीटें देगा। प्रोफेसर भागी ने आश्वासन दिया है कि वे ईडब्ल्यूएस सीटों को अवश्य लेकर आएंगे और जो एडहॉक शिक्षक कॉलेजों से डिस्प्लेसमेंट हुए हैं और जहाँ एससी/एसटी व ओबीसी कोटे की सीटें कम हुई है उनकी पूर्ति कराई जाएगी।

ईडब्ल्यूएस सीटों के बढ़ने से सभी वर्गो के अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत --- डॉ. हंसराज सुमन ने बताया है कि कॉलेजों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों के लिए ईडब्ल्यूएस सीटों के मिलने पर समाज के सभी कमजोर वर्गों के शिक्षकों के साथ सामाजिक न्याय होगा। उनका यह भी कहना है कि शिक्षा मंत्रालय से सीटें मिलने के बाद कॉलेजों को फिर से रोस्टर रजिस्टर तैयार कर विश्वविद्यालय प्रशासन से पास कराकर पदों को विज्ञापित किया जाएगा। उनका कहना है कि किन्हीं कारणों से स्थायी नियुक्ति के समय आरक्षित वर्गो व सामान्य वर्गों के शिक्षक डिस्प्लेसमेन्ट हुए है उन्हें इन पदों पर अवसर दिया जाएगा। फोरम की पहली प्राथमिकता है रोस्टर के कारण पदों के घटने से जो शिक्षकों बाहर हुए पहले उन शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। डॉ.सुमन ने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार के पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से मांग की है कि दिल्ली सरकार के इन कॉलेजों में भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए यूजीसी और दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश जारी कर स्थायी सहायक प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति कराए, क्योंकि यहाँ पर भी पिछले एक दशक से स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है।

दिल्ली सरकार के कॉलेजों में भी हो स्थायी नियुक्ति -- प्रोफेसर भागी से फोरम के चेयरमैन डॉ.सुमन ने यह भी मांग रखी कि वे दिल्ली सरकार के पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों में भी जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराएं। डॉ.सुमन ने बताया है कि इन कॉलेजों में पढ़ाने वाले एडहॉक शिक्षकों की नियुक्ति स्थायी रूप में दूसरे कॉलेजों व अन्य विश्वविद्यालयों में हो जाने के कारण यहाँ पर गेस्ट टीचर्स व एडहॉक टीचर्स के सहारे ये कॉलेज चल रहे हैं। यहाँ पर पिछले एक दशक से शिक्षकों व कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है। प्रो.भागी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि दिल्ली सरकार के बचे हुए कॉलेजों में भी स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू कराई जाएगी। उन्होंने बताया है कि कॉलेजों में स्थायी नियुक्ति, पदोन्नति के साथ पेंशन व अन्य मुद्दों पर तीव्र गति से कार्य हो रहा है, जहाँ 4700 स्थायी शिक्षक व 17 हजार यूनिट से अधिक पदोन्नति हुई है, विश्वविद्यालय / कॉलेजों में यह प्रक्रिया जारी है।

चौथे सप्ताह में भी दर्शकों को लुभा रही बिन्नी एंड फैमिली

सुषमा रानी

नई दिल्ली। बिन्नी एंड फ़ैमिली अपनी रिलीज़ के चौथे सप्ताह में है और इसे अभी भी दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। कलाकार सिनेमाघरों में प्रशंसकों से मिलने के लिए दिल्ली में हैं, जो दर्शकों के साथ मजबूत जुड़ाव का संकेत देता है। कलाकारों और दर्शकों के बीच इस तरह की बातचीत फिल्म की लोकप्रियता को बढ़ा सकती है और अक्सर फिल्म के सिनेमाघरों में चलने के दौरान रुचि बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। दिल्ली में निर्देशक संजय त्रिपाठी, राजेश कुमार, चारु शंकर, नमन त्रिपाठी

महावीर जैन, फिल्म ₹बिन्नी एंड फैमिली₹ के निर्माता फिल्म के प्रति दर्शकों के समर्थन पर पूरा भरोसा जताया। यह कहकर, ₹मुझे अपने दर्शकों पर पूरा भरोसा है,₹ उनका संभवतः यह मतलब है कि उन्हें भरोसा है कि दर्शक फिल्म की सराहना और समर्थन करना जारी रखेंगे, और रिलीज के चौथे सप्ताह में भी इसकी सफलता में योगदान देंगे। फिल्म निर्माताओं का इस प्रकार का आशावाद अक्सर सकारात्मक स्वागत और फिल्म और उसके दर्शकों के बीच मजबूत संबंध का प्रतिबिंब होता है।

करवा चौथ के अवसर पर सुहागनों के लिए फ्री मेहंदी कैंप

सुषमा रानी

त्यौहार जीवन में एक नया संचार करते हैं खुशियों का हिंदुस्तान में समय-समय पर कई त्योहार मनाए जाते हैं उसी में एक त्यौहार है करवा चौथ। करवा चौथ महिलाओं का एक विशेष त्यौहार है जिसमें वह निर्जला व्रत रखकर सिंगार करके पूजा अर्चना करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है जगह-जगह मेहंदी, चूड़ी अन्य सिंगर के समान मिलते हैं उसी कड़ी में हमने आज करवा चौथ के शुभ अवसर पर हमने एक विशेष फ्री मेहंदी कार्यक्रम पटपटगंज विधान सभा में आयोजन किया, यह कहना है पटपड़गंज विधानसभा से समाजसेवी जितेंद्र का मेहंदी कार्यक्रम जिसे पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में समाज की महिलाओं और युवतियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और अपनी खुशी को मेहंदी की सुंदर डिज़ाइनों के माध्यम से प्रकट किया।

दंगों में विदेशी शक्तियों का बहुत बड़ा योगदान, यूपी के पूर्व डीजीपी डॉ. विक्रम सिंह ने दंगों पर जानिए क्या कहा

परिवहन विशेष न्यूज

दंगों की जड़ में सिर्फ़ आंतरिक कमज़ोरी ही नहीं बल्कि विदेशी ताक़तों का भी बड़ा हाथ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP डॉ. विक्रम सिंह ने दैनिक जागरण से ख़ास बातचीत में कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। जानिए दंगों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए और समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए।

राजस्थान का चितौड़गढ़ हो, महाराष्ट्र का भिवंडी हो, कर्नाटक का मांड्या हो या फिर उत्तर प्रदेश का बहराइच। अवसर गणेशोत्सव का हो या रामनवमी या फिर विजयादशमी का। हाल के दिनों में देश के कई शहरों में धार्मिक शोभायात्रा या विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक तनाव और दंगे हुए। लोगों की जान गई। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। सरकारी व निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। सामाजिक समरसता और भाईचारा खत्म हुआ। ये दंगे अचानक भड़के या प्रायोजित कराए गए? इनके पीछे विदेशी ताकतें तो काम नहीं कर रही हैं? राजनीतिक लाभ के लिए तो दंगे नहीं कराए जा रहे हैं? इस गंभीर मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉ. विक्रम सिंह से दैनिक जागरण के गौतमबुद्ध नगर जिला प्रभारी अवनीश मिश्र ने विस्तृत बातचीत की। प्रस्तुत हैं मुख्य अंश...

बार-बार दंगे क्यों होते हैं?

जिस तरह से आंतरिक कमजोरी की वजह से शरीर में बार-बार इंफेक्शन होते हैं, उसी तरह सुरक्षा-व्यवस्था में सामर्थ्य, स्फूर्ति और क्रियाशीलता एवं समस्या का मूल्यांकन करते हुए उसका निराकरण करने की कमी की वजह से बार-बार दंगे होते हैं।

कुछ ऐसे खास इलाके ही क्यों हैं जहां बार-बार दंगे होते हैं?

जहां दंगे का इतिहास रहा हो, जहां पर जनसंख्या को लेकर कुछ समस्याएं रही हों, जो क्षेत्र विवादग्रस्त रहे हों, उसको संवेदनशील कहते हैं। उत्तर प्रदेश में 17 जनपद संवेदनशील हैं। इन जनपदों को चिह्नित किया जाना चाहिए कि ये किन कारणों से संवेदनशील हैं? क्या कोई विवाद है? क्या पहले किसी तरह के मसले हुए हैं? क्या पहले कोई सांप्रदायिक घटना हुई हैं, जिसको लेकर आज भी तनाव विद्यमान है? कहीं-कहीं पर अगर आप एक-दूसरे को थप्पड़ मार दें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कहीं पर अगर हम जरा सा कह दें जय श्रीराम, वहां दंगा हो जाएगा। चाकू चल जाएगा। इसका क्या कारण है? अंग्रेजी में हम कहते हैं कम्युनल थ्रेसहोल्ड यानी सांप्रदायिक सहिष्णुता। जब सांप्रयादिक सहिष्णुता का स्तर बहुत निम्न हो जाता है तो बर्दाश्त करने का सामर्थ्य बहुत कम हो जाता है। यह काम पुलिस-प्रशासन का है कि वह सुनिश्चित करें कि तनाव बाहर आए। जो शिकायतें हैं, उनको दूर किया जाए। सुनिश्चित करें कि इस तरह का कोई घटनाक्रम न हों। यह शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी है। शासन की मुट्ठी फौलाद की होनी चाहिए। उसके ऊपर मखमल चढ़ा होना चाहिए। शरीफों के लिए मखमल दिखाई पड़े। बवालियों के लिए मखमल उतार कर लोहे का पंजा बन जाए और उनको नेस्तनाबूद कर दे।

बहराइच में जो हुआ वह क्यों हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

दंगों में कुछ लोगों का स्वार्थ निहित होता है। वह लोग इससे लाभान्वित होते हैं। इसमें कुछ यूट्यूब चैनल, कुछ टीवी चैनल, कुछ समाचार पत्र, कुछ दान देने वाले, कुछ दान लेने वाले शामिल हैं। जाकिर नाइक जैसे लोग और कुछ राजनीतिक दल इससे लाभान्वित होते हैं। इनके लाभ समाप्त कर दीजिए। दंगों में 50 प्रतिशत कमी आ जाएगी।

बहराइच में मारे गए युवक के साथ जिस तरह की बर्बरता की गई है, वह दंगाइयों की किस मानसिकता का परिचायक है?

यह जिहादी मानसिकता का परिचायक है। प्रतिशोध की भावना भी है। मृतक ने जो किया वह भी उचित नहीं था, वह भी अपराध था। कोई अपराध करता है तो कानून के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन प्लास से नाखून उखाड़ लेना, करंट लगाना समझ से परे है।

क्या बहराइच में जो हुआ उसे रोका जा सकता था?

पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन अगर दंगे के सौ प्वाइंट थे तो उसको 10 प्वाइंट तक सीमित कर सकते थे। 90 प्वाइंट बचा सकते थे। हर दंगा रोका नहीं जा सकता है, लेकिन दंगे से वैसे ही निपटना चाहिए जैसे सिगरेट के बट को जूते के नीचे रगड़कर बुझाया जाता है ताकि चिंगारी ऊपर नहीं आ सके। जो शरारती तत्व हैं, उन्होंने यदि एक करोड़ रुपया झोंक दिया बहराइच में और कहा कि यह करना है। वह तो फिर होना ही है, लेकिन वह होना है तो उसके बाद पुलिस को सौ सुनार की एक लोहार की वाली स्थिति करनी चाहिए। आपको जो करना था कर लिया। आपने धौंस दे दी। धौंस का जवाब अब देखिएगा।

क्या दंगे अचानक भड़कते हैं? या फिर पूर्व की घटनाओं के मद्देनजर इसके होने की आशंका में दोनों पक्ष पहले से तैयार रहते हैं?

नहीं। दंगे अचानक नहीं भड़कते हैं। दंगा होने से पहले एक वातावरण दिखाई देता है। सुबह निकलेंगे तो हवा में तनाव महसूस होगा। पुलिसिया भाषा में इसे कहते हैं कि आज हवा ठीक नहीं है। लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होगी। राशन ज्यादा खरीदा जा रहा होगा। कर्फ्यू की तैयारी की जा रही होगी। इससे साफ है कि दंगे की तैयारियां पहले से हो जाती हैं। इस पर पुलिस अधिकारियों को तुरंत एक्शन मोड में आ जाना चाहिए। आंतरिक सुरक्षा योजना में स्कीमें बनी हैं। उन स्कीमों को लागू करना चाहिए। गश्त बढ़ाकर नाकेबंदी करनी चाहिए। वाच टावर व पिकेट लगाना चाहिए। कहीं कोई संदिग्ध दिखाई पड़े तो चेकिंग की जानी चाहिए।

क्या दंगे आजादी के बाद की परिघटना है या फिर इसका इतिहास भारत पर मुस्लिम शासन से शुरू होता है?

दंगों की श्रृंखला आज की नहीं है। जमाने से चली आ रही है। आजादी के पहले तो आए दिन दंगे होते थे। विशेषकर वर्ष 1942 के बाद। नोआखाली ले लीजिए या बंगाल में सुहरावर्दी की सीधी कार्रवाई। मोपला या केरल दंगा। 1861 का दंगा तो डाक्यूमेंटेड है। गणेश शंकर विद्यार्थी की कानपुर के बड़े दंगे में ही हत्या हुई थी।

> निहित स्वार्थ की एक लाबी है और यह बहुत बड़ा व्यवसाय है। दंगा और दंगा होना यह बहुत बड़ा व्यवसाय है। यूट्यूबर्स और कुछ चैनेल्स की बन आती है। उनकी टीआरपी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में दंगा हुआ था तो कहां-कहां से दान देने वाले चले आए थे। कहां-कहां से फरिश्तों का आगमन हो गया था। ये दंगे का एक बिजनेस माडल है। मेरा परामर्श होगा कि अनावश्यक रूप से बाहरी तत्वों के आवागमन पर प्रतिबंध होना चाहिए। अवांछनीय तत्व जो अफवाह फैलाते हैं, जो हिंसा भड़काते हैं, उनके ऊपर कहर बन के टूट पड़ें।

क्या दंगे इसलिए नहीं रुक रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष विजेता की मानसिकता से उबर नहीं पा रहा है?

किसकी क्या मानसिकता है, उसको वह मुबारक हो। शासन-प्रशासन किस दिन काम आएगा। एक व्यक्ति कहता है कि हत्या करना या बलात्कार करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है तो दवा की पुड़िया शासन-प्रशासन के पास है ही। इलाज तो शुरू कर दीजिए। लाल दवा से शुरू कीजिए। होम्योपैथी तक आइए। उसके बाद थोड़ा हल्का सा चीरा लगाइए, फिर बाइपास सर्जरी तक का तो इलाज है। रासुका व गैंगस्टर के अंतर्गत ऐतिहासिक कार्रवाई हो सकती है। शासन से कोई लड़ नहीं सकता है।

दोनों समुदायों के बीच खाई क्यों बढ़ती जा रही है?

इसका कारण है इंटरनेट मीडिया। भ्रामक प्रचार और उस प्रचार को निष्क्रिय करने के बारे में शासन की कोई ठोस नीति नहीं है। यूट्यूबर्स के ऊपर नियंत्रण, भड़काऊ बयान के ऊपर कार्रवाई। कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। इंटरनेट मीडियो के आने से पहले यानी वर्ष 2010 के पहले इतनी भयावह स्थिति नहीं होती थी, जितनी अब हो रही है।

इस खाई को पाटने के लिए पुलिस और प्रशासन की क्या भूमिका हो सकती है?

पुलिस-प्रशासन को तकनीकी माध्यमों के सहारे ही नहीं रहना चाहिए। उन्हें अधिक से अधिक गणमान्य लोगों से मिलते रहना चाहिए। उनका एक समूह बनाकर रखना चाहिए ताकि सूचनाओं का आदान-प्रदान होता रहे। शांति समितियों में दोनों समुदायों में पकड़ रखने वाले लोगों को शामिल करना चाहिए। उनकी मदद से दोनों समुदाय को लोगों में पैठ बनानी चाहिए। पूर्व में 10 साल पहले हुए दंगों वाले स्थानों पर त्योहार व जुलूस के समय ऐसे लोगों को खड़ा रखना चाहिए ताकि भ्रामक सूचना आने पर आपस में समझ कर दूर किया जा सके।

दंगों के पीछे क्या कोई विशेष मानसिकता काम कर रही है?

निहित स्वार्थ की एक लाबी है और यह बहुत बड़ा व्यवसाय है। दंगा और दंगा होना यह बहुत बड़ा व्यवसाय है। यूट्यूबर्स और कुछ चैनेल्स की बन आती है। उनकी टीआरपी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में दंगा हुआ था तो कहां-कहां से दान देने वाले चले आए थे। कहां-कहां से फरिश्तों का आगमन हो गया था। ये दंगे का एक बिजनेस माडल है। मेरा परामर्श होगा कि अनावश्यक रूप से बाहरी तत्वों के आवागमन पर प्रतिबंध होना चाहिए। अवांछनीय तत्व जो अफवाह फैलाते हैं, जो हिंसा भड़काते हैं, उनके ऊपर कहर बन के टूट पड़ें। यूपी में रासुका और यूपी गैंगस्टर एक्ट के रूप में दो सशक्त कानून हैं। उनका भरपूर प्रयोग करें। बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है।

क्या आपको ऐसा भी लगता है कि जो व्यवस्था है उसे बिगाड़ने में विदेशी ताकतें काम करती हैं?

क्यों नहीं? विदेशी शक्तियों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर रोहिंग्या श्रीनगर, पुलवामा, भावनगर, मुंबई पहुंच सकता है तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी शक्तियां हैं जो ऐसी ताकतों को हवा दे रही हैं। वहीं ताकतें जाकिर नाइक जैसे लोगों के पीछे हैं, जो कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। युवाओं को बरगला रहे हैं। हैदराबाद से आया एक व्यक्ति नोटों के थैले लेकर बनभूलपुरा में बांट रहा था, वह विदेशी शक्तियों का ही प्रसाद है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते तो आपने भी सुने होंगे। आपने यह भी सुना होगा कि केरल में हमास के डिप्टी लीडर की वीडियो कांफ्रेंसिंग कराई गई थी। हमास जिंदाबाद के नारे भी आपने सुने होंगे। आपका मतलब क्या है हमास से। आपका मतलब क्या है कि फिलिस्तीन से। बांग्लादेश में जो हो रहा है, उसके बारे में तो आपने एक शब्द नहीं कहा। रोहिंग्याओं के लिए चंदा उगाही कर रहे हैं। यहां विदेशी ताकतों का स्पष्ट आयाम दिखाई पड़ रहा है। हमें केंद्र सरकार से बड़ी उम्मीदें थीं कि इस पर प्रभावी कार्रवाई होगी, लेकिन लुंजपुंज तरीके से ढुलमुल कार्रवाई हो रही है। विदेशी ताकतों की संलिप्तता के तीन उदाहरण दिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमास जिंदाबाद, हमास के डिप्टी लीडर का वीडियो कांफ्रेंसिंग। इसका क्या मतलब है। पाकिस्तान के जिहादी मौलाना के बेटे की तस्वीर बरेली में लगाने का क्या मतलब है? इससे साबित होता है कि विदेशी ताकतें देश को बांटने के लिए काम कर रही हैं।

राजनीतिक हित के लिए भी क्या दंगे कराए जाते हैं?

दंगों से कुछ लोग लाभान्वित होते हैं। कुछ नेता राजनीतिक ध्रुवीकरण करते हैं और ये आज की बात नहीं है। यह पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह ऐसा न होने दे। हम लोग जब पुलिस की नौकरी में थे, तो कह देते थे कि आप में दम है तो दंगे करा दीजिए और अगर हममें दम होगा तो ऐसा कर देंगे कि यह आपका आखिरी दुष्प्रचार होगा। इसके बाद न तो चुनाव लड़ पाएंगे न जिंदा रहेंगे। मिट्टी में मिल जाएंगे।

धर्मगुरुओं की दंगे के दौरान क्या भूमिका रहती है और क्या होनी चाहिए?

धर्मगुरु केवल एक लाइन की अपील किया करें कि कानून का पालन करें। प्रशासन पर विश्वास करें। हम सब भाई-भाई हैं। इसके अलावा अगर विद्वता छांटने की कोशिश की कि हमारा धर्म हमें ये आज्ञा देता है कि हम ये कर सकते हैं और हम वो कर सकते हैं और अगर यह सब संवैधानिक नहीं है तो धर्मगुरु सलाखों के पीछे जाएं। संविधान से ऊपर न कोई धर्मगुरु है और न कोई और चीज है।

दंगों के बाद बनाए गए आयोगों की संस्तुतियों को किस रूप में देखते हैं?

2014 में मुजफ्फरनगर दंगा। 1980 में मुरादाबाद दंगा या मलियाना-हाशिमपुर दंगा, क्या आज तक किसी आयोग की रिपोर्ट पर कुछ कार्रवाई हुई है? आयोग बनाने का एक मकसद होता है। वह तात्कालिक होता है। दीर्घकालिक नहीं होता है। दंगे हुए। समितियां बनीं, सस्तुतियां आईं। रद्दी की टोकरी में गईं। हरियाणा में जाट दंगा हुआ। प्रकाश सिंह समिति बनी। प्रकाश सिंह ने कहा कि हमने संस्तुति की, लेकिन उसके पर एक फीसद पर भी कार्रवाई नहीं हुई।

दंगों को नियंत्रित करने की अल्पकालिक कार्ययोजना क्या हो?

पहले तो कोशिश हो कि दंगा हो न और यदि हो जाता है तो जो-जो जिम्मेदार हैं, उनको ऐसा रगड़ दीजिए कि लोग पूछें कि साहब यह जेल गए थे आखिर हुआ क्या। ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार सलाखों के पीछे हो।

दंगों की पुनरावृत्ति रोकने की दीर्घकालिक कार्ययोजना क्या हो?

आंतरिक सुरक्षा योजना का पूर्वाभ्यास, अपनी तैयारी, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और उच्च कोटि की अभिसूचना। अभिसूचना पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बतौर उदाहरण कहीं पर भी जन समागम होता है तो उसमें एक प्रतिशत पुलिस कर्मी होने ही चाहिए। सुंदरकांड का पाठ हो, अखंड रामायण हो, शुक्रवार की नमाज हो या कोई जमात हो, तो उसमें एक प्रतिशत पुलिसकर्मी होने ही चाहिए। उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। कहां क्या पक रहा है, इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अंग्रेजों के जमाने में तो कोई बाहरी व्यक्ति दिख जाता था तो उसके आने के मकसद, ठहरने के स्थान व मिलने वालों का विवरण खंगाल लिया जाता था। वह कितने लोग थे, कहां ठहरे, कितनी देर रुके, किससे मिले, क्या पहने थे। आज पुलिस भगवान भरोसे हैं। आइपैड और मोबाइल के भरोसे है। उससे क्या सूचनाएं मिलेंगी।

इन सबके बीच समाज की भूमिका क्या भूमिका होनी चाहिए?

परिपक्वता। समाज को समझना होगा कि किसी भी दंगे से सिवाय अपराधी के किसी का भला नहीं हुआ है। इससे सिर्फ धूर्त प्रवृत्ति के राजनीतिक व्यक्ति व अपराधी ही लाभान्वित होते हैं। इनके खेल को समझें। देश को आगे बढ़ना है। शांति-व्यवस्था होगी, तभी आर्थिक विकास होगा। रोजगार आएंगे। सबका भला होगा।

कांग्रेस के साथ ही आगे बढ़ेगा अखिलेश यादव का समाजवाद

अजय कुमार

सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि उपचुनाव के लिए हुए समझौते के तहत अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट के साथ गाजियाबाद सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। वैसे इसे सपा का डैमेज कंट्रोल भी माना जा रहा है।?

कांग्रेस आलाकमान और गांधी परिवार भले ही यूपी से बाहर समाजवादी पार्टी को अपने तेवर दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चाह कर भी कांग्रेस को अनदेखा नहीं कर पा रही है। इसे समाजवादी पार्टी की सियासी मजबूरी कहें या फिर समय की मांग जिसकी वजह से हरियाणा में खाली हाथ रहने के बावजूद समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस के साथ रिश्ता बनाए रखेगी। यूपी में उपचुनाव वाली 10 सीटों में सपा 8 पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। शेष दो सीटें उसने कांग्रेस के लिये छोड़ दी हैं। जबकि कांग्रेस पांच सीटों की मांग कर रही थी, वैसे पांच सीटों वाली उसकी मांग तर्कसंगत भी नहीं थी।

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने का फैसला किया है। यूपी में उपचुनाव वाली 10 सीटों में सपा 8 पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि उपचुनाव के लिए हुए समझौते के तहत अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट के साथ गाजियाबाद सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। वैसे इसे सपा का डैमेज कंट्रोल भी माना जा रहा है। हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार के अगले दिन ही सपा ने यूपी में छह सीटों पर उपचुनाव के उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। इसे कांग्रेस के नेता नाराज हो गये थे। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडेय ने भी सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत से इंकार कर दिया था। सूत्रों का कहना है कि गत दिनों जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण के दौरान राहुल व अखिलेश की मुलाकात के बाद सीट बंटवारे पर सहमति बनी। वैसे कइ बार अखिलेश कह चुके हैं कि यूपी में इंडिया गठबंधन जारी रहेगा।

बात उम्मीदवारों की कि जाये तो समाजावादी पार्टी ने बसपा के राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली की बेटी सुंबुल राणा को मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। गत दिवस स्थानीय नेताओं व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सुंबुल का नाम तय किया है। सुंबुल बसपा के पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू हैं। कादिर राणा इस समय सपा में हैं। मुनकाद और कादिर का सियासी रिश्ता 2010 में पारिवारिक रिश्ते में बदला था, तब कादिर भी बसपा में थे। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले कादिर सपा में शामिल हो गए थे। मीरापुर सीट सपा के साथ गठबंधन में रालोद ने जीती थी। हालांकि, लोकसभा चुनाव के पहले रालोद ने भाजपा का साथ पकड़ लिया। मीरापुर के विधायक चंदन चौहान के बिजनौर से सांसद बनने के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। सपा अब तक उपचुनाव वाली सात सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इसमें छह टिकट नेताओं के परिवार में ही गए हैं। अल्पसंख्यकों की भागीदारी का संदेश देने के लिए अखिलेश ने अब तक तीन टिकट मुस्लिमों को दिए हैं।

बहरहाल, नौ विधान सभा सीटों पर चुनाव के लिये सभी दल पूरी मेहनत कर रहे हैं, वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव टलने को लेकर सपा और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप बढ़ता जा रहा है। अब भाजपा ने सपा पर चुनाव टालने का आरोप लगाया है। जब मिल्कीपुर का चुनाव घोषित नहीं किया गया तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरा था। और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके तंज किया था कि जिसने जंग टाली है, उसने जंग हारी है। वहीं, मिल्कीपुर के पूर्व विधायक गोरखनाथ ने इसका जबाव देते हुए कहा है कि भाजपा नहीं, बल्कि सपा डर गई है। यही वजह है कि उन्होंने (गोरखनाथ) अपनी याचिका वापस लेने की अपील कोर्ट से की। कोर्ट में गुरुवार 17 अक्टूबर को सुनवाई थी। मैं वहां पहुंचा तो देखा कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद वहां एक दर्जन वकील भेज दिए हैं। इस बात पर बहस होने लगी कि ऐसे आप याचिका वापस नहीं सकते। इससे साफ है कि समाजवादी पार्टी डर गई है और वह चुनाव नहीं चाहती। कुल मिलाकर कांग्रेस और सपा के रिश्तों की बात की जाये तो अभी ऐसा नहीं लगता है कि सपा और कांग्रेस की राहें जुदा होने वाली है। फिलहाल अखिलेश का समाजवाद कांग्रेस के साथ ही आगे बढ़ेगा।

वायु प्रदूषण बढ़ने पर सांस रोगियों की मुसीबत बढ़ी, गाजियाबाद में दो की मौत

बढ़ते वायु प्रदूषण ने गाजियाबाद में सांस के मरीजों की मुसीबत बढ़ा दी है। सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी में सांस और दमा के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शुक्रवार को ही दो मरीजों की मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे मरीजों को वायु प्रदूषण बढ़ने पर अधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है।

गाजियाबाद। शहर की हवा खराब होने के साथ ही सांस के रोगियों की मुसीबत बढ़ने लगी है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी में सांस और दमा के रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिला एमएमजी अस्पताल द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कैलाशनगर के रहने वाले 65 वर्षीय देशराज की उपचार के दौरान मौत हो गई।

सीएमएस के अनुसार देशराज सीओपीडी का मरीज था। इसके अलावा कैलाश नगर के रहने वाले 36 वर्षीय राजू को इमरजेंसी में मृत घोषित किया गया है। राजू भी टीबी और सांस का मरीज था। इसके अलावा रेलवे स्टेशन साहिबाबाद से 24 वर्षीय अमित को मृतावस्था में लाया गया।

कितने मरीज पहुंचे अस्पताल

ओपीडी में शुक्रवार को कुल 2247 मरीज पहुंचे। इनमें बुखार के 539 और सांस व बुखार की शिकायत पर 392 बच्चे पहुंचे। इमरजेंसी में सांस के 23 मरीज पहुंचे। 42 मरीजों में 34 का चेस्ट एक्स-रे कराया गया। संयुक्त अस्पताल की ओपीडी में कुल 834 मरीज पहुंचे। इनमें 88 बीमार बच्चे शामिल हैं। 45 बच्चों समेत 312 लोगों ने एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाई है।

मरीजों को बरतनी चाहिए सावधानी

क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) फेफड़ों और वायुमार्ग की बीमारी है, जो सांस को रोकता है। सीओपीडी वाले लोगों में वायुमार्ग में सूजन और निशान होते हैं, उनके फेफड़ों में वायु थैलियों को नुकसान होता है या दोनों होते हैं। वातस्फीति और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस दोनों सीओपीडी के रूप हैं। ऐसे मरीजों को वायु प्रदूषण बढ़ने पर अधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। बिना मास्क लगाए घर से नहीं निकलना चाहिए। -डॉ. आशीष अग्रवाल, पल्मोनालॉजिस्ट

लोनी की हवा सबसे जहरीली

जिले में लोनी की हवा सबसे अधिक जहरीली हो गई है। शुक्रवार को लोनी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) बेहद खराब श्रेणी में 324 दर्ज किया गया। बेहद खराब श्रेणी में हवा देख नगर पालिका परिषद ने डीएलएफ भड़ाना ग्रुप के पास खुले में निर्माण सामग्री बेचने वालों पर 90 हजार का जुर्माना लगाया। साथ ही लाखों की निर्माण सामग्री भी जब्त की।

वहीं, 258 एक्यूआई के साथ जिले की हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई। ग्रेप (GRAP) लागू होने पर जिले में लोनी की हवा सबसे अधिक खराब हो गई है। यह इलाका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में भी शामिल है। औद्योगिक इकाइयों, निर्माण गतिविधियों और सड़कों पर उड़ती धूल को प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण माना जाता है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य विभागों के अधिकारी प्रदूषण की रोकथाम करने में फेल साबित हो रहे हैं। मानकों का उल्लंघन करने वाले इक्का-दुक्का लोगों पर ही जुर्माना लगाकर खानापूरी की जा रही है। जिससे लोगों को प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है।

- :सौजन्य :-
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

OKINAWA SCOOTERS
Power the Change
BLACKLIST

ब्लैकलिस्टिंग नोटिस के खिलाफ ओकिनावा की याचिका खारिज

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण कंपनी ओकिनीवा ऑटोटेक के खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके द्वारा भारत सरकार ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया था [ओकिनावा ऑटोटेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ]।

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि रिट अदालत केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही कारण बताओ नोटिस में हस्तक्षेप कर सकती है, जैसे कि जब नोटिस अधिकार क्षेत्र के बिना जारी किया गया हो या जहां कानून का दुरुपयोग हो।

इस मामले में न्यायालय ओकिनावा के इस दावे से सहमत नहीं था कि कारण बताओ नोटिस पूर्वाग्रह से या काली सूची में डालने के लिए 'पूर्वनिर्धारित मन' से जारी किया गया था। इसलिए न्यायालय ने केंद्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा 11 सितम्बर को जारी कारण बताओ नोटिस को ओकिनावा द्वारा दी गई चुनौती को खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा, ₹इस अदालत को इस स्तर पर कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं दिखता। किसी भी मामले में अपीलकर्ता कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करते समय प्राधिकरण के समक्ष अपनी सभी आपत्तियां उठा सकते हैं तथा वे अपनी सभी आपत्तियां भी प्रस्तुत कर सकते हैं।"

ओकिनावा को इससे पहले अक्टूबर 2023 में मंत्रालय द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया था, जब सरकार ने निष्कर्ष निकाला था कि ईवी कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और विनिर्माण, फेम-II योजना और चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम दिशानिर्देश की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रही है।

इस योजना और दिशा-निर्देशों को भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत शुरू किया गया था। इस पहल के तहत सब्सिडी पाने वाले निर्माताओं को समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने वाहन मॉडल के कुछ हिस्सों को स्वदेशी बनाना आवश्यक था।

ओकिनावा ऑटोटेक के इलेक्ट्रिक स्कूटर को 2019 में सबसे पहले फेम-II सब्सिडी प्रोत्साहन मिला था। इस योजना के तहत कंपनी द्वारा दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के आरोपों के मद्देनजर सरकार ने पहले दी गई सब्सिडी वापस लेने की कार्यवाही शुरू की।

ओकिनावा ने अंततः 2023 में अपने पंजीकरण रद्द करने के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष चुनौती दी, जिस पर निर्णय लंबित है। इस बीच मंत्रालय ने ओकिनावा के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर कंपनी को काली सूची में डालने की कार्रवाई का प्रस्ताव दिया।

ओकिनावा ने कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी। एकल न्यायाधीश द्वारा उक्त चुनौती को खारिज करने के बाद ओकिनावा ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की।

वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने ओकिनावा की ओर से दलीलें पेश कीं जिसमें कहा गया कि कारण बताओ नोटिस तब तक जारी नहीं किया जाना चाहिए था, जब तक कि पंजीकरण रद्द करने की उनकी चुनौती अभी भी लंबित है।

ओकिनावा ने बताया कि कारण बताओ नोटिस उसके विरुद्ध जारी पंजीकरण रद्द करने के आदेश तथा फेम-II और पीएमपी दिशा-निर्देशों के कथित उल्लंघन पर आधारित था।

इसने यह भी तर्क दिया कि चूंकि जिस प्राधिकरण ने पंजीकरण रद्द करने का आदेश दिया था, उसी ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ओकिनावा के खिलाफ पक्षपात का तत्व है। ईवी कंपनी ने तर्क दिया कि प्राधिकरण ने ओकिनावा को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव करते समय पूर्व निर्धारित मन से नोटिस जारी किया हो सकता है।

केंद्र सरकार ने पक्षपात के आरोपों से इनकार किया। अन्य दलीलों के अलावा, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एन वेंकटरमन ने कहा कि ओकिनावा एकमात्र ऐसी कंपनी नहीं है, जिसके सब्सिडी दावों की वास्तविकता पर संदेह होने के बाद कार्रवाई की जा रही है। एएसजी ने तर्क दिया कि सब्सिडी वसूलने की कार्यवाही पांच अन्य कंपनियों के खिलाफ भी शुरू की गई थी।

कोर्ट ने अंततः ओकिनावा की दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसी प्राधिकरण को कारण बताओ नोटिस जारी करने से रोकता हो और इस पहलू से यह नहीं लगता कि इसमें व्यक्तिगत पक्षपात है।

अदालत ने कहा, ₹ इसके अलावा, अपीलकर्ता को अपना जवाब दाखिल करने का अवसर दिया जाएगा, जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।₹

न्यायालय ने आगे कहा कि ओकिनावा की याचिका के लंबित रहने से उसके पंजीकरण रद्द करने को चुनौती देने पर ब्लैकलिस्ट करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने में बाधा नहीं आएगी। न्यायालय ने ओकिनावा की अपील को खारिज कर दिया।

न्यायालय ने स्पष्ट किया, ₹ यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां मामले के गुण-दोष पर किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति के समान नहीं होंगी। पक्षों के अधिकार और तर्क खुले छोड़े गए हैं।₹

वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा, अधिवक्ता मनीष बिश्नोई, अनुराग भट्ट, लोकेश पाठक, वैभव विजयवर्गीय और अंकुर गुप्ता ओकिनानवा की ओर से पेश हुए।

एएसजी एन वेंकटरमन, केंद्र सरकार के स्थायी वकील अनुराग अहलूवालिया, अधिवक्ता अमीश टंडन, अनुश्री कुलकर्णी, वैष्णवी, अमित आचार्य, कौशल जीत कैत, हृदयांशी शर्मा के साथ केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए।

फर्रुखाबाद में अब बगैर वेरीफिकेशन के मुख्य मार्गों पर नहीं दौड़ सकेंगे ई-रिक्शा

परिवहन विशेष न्यूज

अपराध नियंत्रण को पुलिस ने नायाब तरीका निकालते हुए ई-रिक्शा के संचालन को लेकर नए नियम बनाए हैं। इसके तहत बगैर वेरीफिकेशन के मुख्य मार्गों पर कोई भी ई-रिक्शा नहीं दौड़ सकेगा। ई-रिक्शा पर मालिक, चालक का पता और मोबाइल नंबर भी अंकित होगा। ई-रिक्शा पर अक्सर कई प्रकार की घटनाएं होने के बाद पुलिस प्रशासन गंभीर हुआ है। मोबाइल गायब होने के ज्यादातर प्रकरण ई-रिक्शा पर ही सामने आ रहे हैं।

शहर में ई-रिक्शा की भरमार है, तीन हजार से अधिक ई-रिक्शा अकेले फर्रुखाबाद शहर में ही चल रहे हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि के इधर-उधर के लोग ई-रिक्शा संचालन में लिप्त हैं। इनकी पहचान हो पाना काफी कठिन हो रहा है। कई जनपदों के लोग भी यहां पर ई-रिक्शा चला कर रहे हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने ई-रिक्शा संचालन के लिए जो नियम बनाए हैं उससे हड़कंप मचा है। इस अभियान में ई-रिक्शा पर मालिक, चालक का पता और मोबाइल नंबर अंकित किया जा रहा है। अभी तक 1100 ई-रिक्शा का वेरीफिकेशन कर मोबाइल नंबर सहित नाम और पता अंकित किया जा चुका है।

इस अभियान के लिए अभी दस दिन का समय और है। ई-रिक्शा चालकों को दिया गया है, निर्धारित अवधि में नाम, पता, मोबाइल नंबर अंकित कराने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय सीमा के भीतर जो ई-रिक्शा चालक बिना वेरीफिकेशन कराये मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का मानना है कि इस अभियान से अवैध रूप से संचालित ई-रिक्शा का संचालन नहीं हो सकेगा। इसके साथ ही आपराधिक पृष्ठ भूमि के जो लोग इस कार्य में लिप्त हैं उन पर भी नकेल कसी जा सकेगी।

एनसीआर में इन जगहों पर 50 ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलने की तैयारी

परिवहन विशेष न्यूज

अगले कुछ महीनों में ई-बसें और अन्य बिजली से संचालित वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण ने शहर में करीब 50 ई-चार्जिंग स्टेशन खोलने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है कि इस बार चार्जिंग स्टेशन खुद प्राधिकरण तैयार कराएगा।

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि जिन जगह ई-चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, उसे लेकर एक बार सर्वे हो चुका है। एक बार और सर्वे कर लोकेशन को अंतिम रूप दिया जाएगा। ये स्टेशन सभी मेट्रो स्टेशन, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे सहित मुख्य सड़कों पर बनाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि कुछ दिनों में इसको लेकर बैठक होगी। इसके बाद एक डीपीआर तैयार कर आला अधिकारियों को दिखाकर मंजूरी ली जाएगी।

नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि अगले कुछ महीनों में नोएडा में 100 से अधिक ई-बसें चलने लगेंगी। इसके अलावा ई-वाहनों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। इसको देखते हुए तैयारी शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि अभी तक जो स्टेशन बने हुए हैं, उनसे प्राधिकरण एक रुपये यूनिट के हिसाब से प्राधिकरण शुल्क लेता है।

करीब चार साल पहले नोएडा में 54 स्थानों पर 162 चार्जिंग मशीनें लगाए जाने के लिए कंपनी ने प्राधिकरण और यूपीपीसीएल के साथ मिलकर सर्वे किया था। करीब तीन साल पहले नोएडा प्राधिकरण की ओर से कनवर्जन्स एनर्जी एफीशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने यह मशीनें लगाईं। कनवर्जन्स एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के मुताबिक शहर में 54 स्थानों पर 69 ई-चार्जिंग मशीन लगाई गई थीं। इनमें से 30 शुरू हो गई थीं, जबकि बाकी बिजली कनेक्शन नहीं मिलने के कारण मामला अटका पड़ा था। खास बात यह है कि पिछले दो-तीन साल में लगे चार्जिंग मशीन अब सिर्फ दिखावा साबित हो रही हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और यूपी सरकार सब्सिडी तक दे रही है, ताकि प्रदूषण नियंत्रित हो सके। ई-कार इस तरह के प्रदूषण को रोकने में कारगर है। प्रति ई-कार से प्रतिवर्ष 4.04 टन कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन की बचत होने का अनुमान है।

मेथनॉल में डीजल-पेट्रोल और एलपीजी की जगह लेने की क्षमता

METHANOL INSTITUTE
International Methanol Seminar

परिवहन विशेष न्यूज

नीति आयोग द्वारा अमेरिका के मेथनॉल इंस्टीट्यूट के सहयोग से नई दिल्ली में 17-18 अक्टूबर 2024 को दूसरे अंतरराष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो का आयोजन किया गया। 2016 में प्रथम सेमिनार की सफलता के आधार पर इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में मजबूत मेथनॉल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना था, जिसमें मेथनॉल की क्षमता पर गहन मंथन किया गया।

नीति आयोग के सलाहकार सुरेंद्र मेहरा ने कई क्षेत्रों में स्थायी ईंधन के रूप में मेथनॉल की अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ₹मेथनॉल न केवल एक वैकल्पिक ईंधन है, बल्कि एक हरित ईंधन है।"

मेहरा ने शिपिंग और परिवहन से लेकर टिकाऊ विमानन ईंधन, खाना पकाने और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए फीडस्टॉक के रूप में मेथनॉल के विभिन्न अनुप्रयोगों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, ₹मेथनॉल और अन्य वैकल्पिक ईंधन इस पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।₹ उन्होंने एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिसमें विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को शामिल किया गया हो।

सेमिनार के आयोजक सदस्य प्रशांत गुरु श्रीनिवास ने डीजल, पेट्रोल और एलपीजी की पूरी तरह जगह लेने के लिए मेथनॉल की क्षमता को दोहराया। उन्होंने नीति आयोग द्वारा 2016 में मेथनॉल कार्यक्रम शुरू करने के बाद से की गई प्रगति पर जानकारी साझा की। उद्योग से जुड़ी कंपनियों के साथ साझेदारी ने मेथनॉल मिश्रणों के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा दिया है, जैसे एमडी15 (मेथनॉल-डीजल मिश्रण) और एम15 (मेथनॉल-पेट्रोल मिश्रण)। किर्लोस्कर और अशोक लीलैंड सहित प्रमुख कंपनियों ने मेथनॉल जेनसेट (Generator Set) और बसें बनाई हैं।

भारत सरकार ने परिवहन ईंधन के रूप में मेथनॉल के लिए पहले ही एक नियामक ढांचा स्थापित कर दिया है और सड़क परिवहन मंत्रालय ने 2018 में इसे व्यवहार्य घोषित किया है।

श्रीनिवास ने कहा, ₹मेथनॉल अर्थव्यवस्था अब अपने कार्यान्वयन चरण में है।₹ उन्होंने नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मेथनॉल-मिश्रित बसों और ट्रकों के लॉन्च की ओर इशारा किया।

भारत वैश्विक स्तर पर मेथनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है, इसलिए सेमिनार ने मजबूत मेथनॉल बुनियादी ढांचा स्थापित करने के महत्व को प्रदर्शित किया। मौजूदा इथेनॉल स्टेशनों की तरह मेथनॉल ईंधन स्टेशन शुरू करने की तैयारी चल रही है, जिससे इस टिकाऊ ईंधन तक आसान पहुंच हो सके। इससे विभिन्न अनुप्रयोगों में मेथनॉल के उपयोग में सुविधा होगी, विशेष रूप से शहरी सार्वजनिक परिवहन में, जहां डीजल की बढ़ती कीमतें वित्तीय संकट पैदा कर रही हैं।

उद्योग जगत के लोगों ने भी यही उम्मीद जताई है। मेटफ्यूल (Metfuel) के मोहित मंडन ने भारत के पहले मेथनॉल डिस्पेंसिंग वाहन के लॉन्च पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य बड़े रसोईघरों में मेथनॉल पहुंचाना और उत्सर्जन को काफी हद तक कम करना है। उन्होंने कहा कि मेथनॉल में नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), सल्फर ऑक्साइड (SOx) या पार्टिकुलेट मैटर नहीं होते हैं, जिससे यह वायु प्रदूषण से जूझ रहे शहरी क्षेत्रों के लिए आदर्श विकल्प बन जाता है।

सेमिनार की महत्वपूर्ण विशेषता वैश्विक सहयोग पर इसका जोर था, जिसमें दुनिया भर के विशेषज्ञों, उद्योग से जुड़े लोगों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को एक मंच पर लाया गया। ज्ञान भागीदार के रूप में मेथनॉल संस्थान के साथ साझेदारी ने मेथनॉल पहल को बढ़ावा देने में साझा विशेषज्ञता के महत्व को रेखांकित किया। जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, मेथनॉल उत्पादन में प्रगति के बारे में चर्चा हुई, जिसमें उच्च राख वाले कोयले को मेथनॉल में परिवर्तित करना और 100 प्रतिशत मेथनॉल पर चलने में सक्षम इंजन विकसित करना शामिल था। अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में भारत सरकार के निवेश का उद्देश्य ऊर्जा परिदृश्य में मेथनॉल को एकीकृत करने के लिए व्यापक ढांचा तैयार करना है।

दूसरा अंतरराष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 ने न केवल कम कार्बन ईंधन के रूप में मेथनॉल की क्षमता को रेखांकित किया बल्कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में इसकी भूमिका पर महत्वपूर्ण चर्चाओं को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में भी काम किया। इसमें एक दर्जन देशों के वक्ताओं ने भौतिक और आभासी रूप से भाग लिया और यह एक टिकाऊ, मेथनॉल-संचालित भविष्य बनाने के प्रयास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।

मेहरा ने आशावादी दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष निकाला, ₹मेथनॉल अर्थव्यवस्था केवल एक कल्पना नहीं है; यह वास्तविकता बन रही है और सरकार, उद्योग और शिक्षाविदों के सामूहिक प्रयासों से भारत स्थायी ऊर्जा समाधानों में अग्रणी हो सकता है।"

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पहले दिन सेमिनार के मुख्य अतिथि थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के. बेरी और नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके सारस्वत के साथ-साथ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और अन्य संगठनों के पदाधिकारी भी सेमिनार में शामिल हुए।

एआई: 21वीं सदी में सीखने को फिर से परिभाषित करना

विजय गर्ग

नए अध्ययन के बारे में एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में टोरंटो विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी एफ्रैम स्टीनबर्ग ने लिखा, जिसे 5 सितंबर को प्रीप्रिंट सर्वर arXiv.org पर अपलोड किया गया था और अभी तक सहकर्मी-समीक्षा नहीं की गई है। इस काम का विचार 2017 में सामने आया। उस समय, स्टाइनबर्ग और एक प्रयोगशाला सहयोगी, तत्कालीन डॉक्टरेट छात्र जोशिया सिंक्लेयर, प्रकाश और पदार्थ की बातचीत में रुचि रखते थे, विशेष रूप से परमाणु उत्तेजना नामक एक घटना: जब फोटॉन एक माध्यम से गुजरते हैं और मिलते हैं अवशोषित, उस माध्यम में परमाणुओं के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाते हैं।

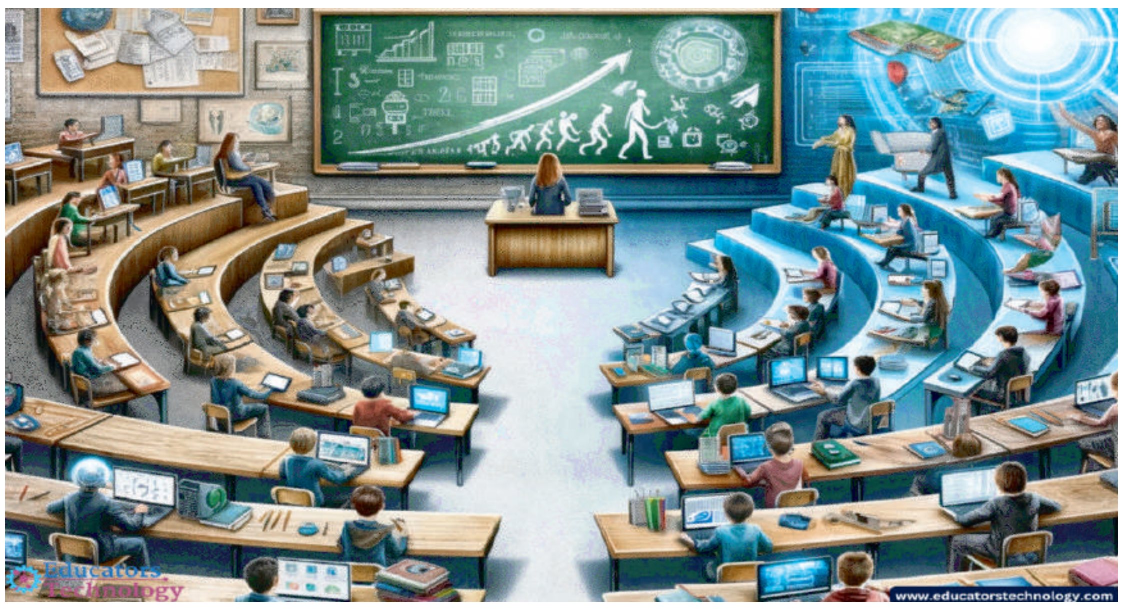

तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से वर्तमान समय और भविष्य समय एक दूसरे में विलीन होने को तैयार हैं विजय गर्ग शिक्षण पद्धतियां और कार्यस्थल की मांगें तेजी से विकसित हो रही हैं, जिससे शैक्षणिक संस्थान बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने वाले नए प्रतिमानों को अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। अब यह तेजी से पहचाना जा रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकी का उपयोग सीखने की प्रकृति को बदल देगा, जैसा कि पिछले 100 वर्षों में कुछ चीजों में हुआ है। यदि कोई छह या सात दशक पहले वापस जाए तो परिवर्तन की मूल प्रकृति और उसकी गति कोई नई बात नहीं है। डिजिटलीकरण प्रक्रिया ने अंकों को सीखने की प्रकृति को बदल दिया है। कैलकुलेटर के उपयोग ने गुणन सारणी को याद करना काफी हद तक अप्रासंगिक बना दिया है। एक बड़ा बदलाव आया जिसने हर गुजरते दशक के साथ इसकी पहुंच और गहराई को बढ़ाया है। कैलकुलेटर से लेकर कम्प्यूटरीकरण और कम्प्यूटरीकरण दक्षताओं के लगातार ऊपर की ओर बढ़ने से न केवल तालिकाएँ और एल्गोरिदम केवल मामूली रूप से प्रासंगिक हो गए, बल्कि लॉग तालिकाएँ भी इतिहास का विषय बन गईं। कक्षा और परीक्षा हॉल में एक यांत्रिक उपकरण की अनुमति देने में कुछ प्रारंभिक अनिच्छा के बाद, सीखने की प्रकृति को नई वास्तविकताओं के साथ समायोजित किया गया। मशीन से जुड़ी वास्तविकता नया प्रतिमान बन गई। सीखने की प्रकृति धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से किसी की स्मृति के माध्यम से काम करने से लेकर मशीनों और उनके एल्गोरिदम के अभ्यस्त होने तक बदल गई। मानसिक सहयोग पर वापस लौटने से मशीन-आधारित समाधानों की ओर रुझान बदल गया। प्रौद्योगिकी में बदलाव के लिए भी सीखने की जरूरत है लेकिन एक अलग क्रम की। रोज़गार बाज़ार में बने रहने के लिए विशेषज्ञता के दोहरेपन की मांग अधिक थी। वास्तव में, मशीनें बोलने के तरीके में एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगीं और इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण रूस में जेट विमान (इलुशिन) के निर्माण में उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रौद्योगिकी मोड और बोइंग विमान में उपयोग की जाने वाली तकनीक होगी। नई वास्तविकताओं की आवश्यकता है जिसे 'नया सीखना' कहा जा सकता है, उसके प्रति नया दृष्टिकोण। अंकगणित, गणित और बहुत कुछ पढ़ाने की प्रकृति में बदलाव आया और कक्षा में कई क्रांतियों से भी बड़ी क्रांति आ गई। इस क्रांति की प्रकृति महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह एक सतत क्रांति थी और आज, यह सीखने वाले को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विभिन्न रूपों के माध्यम से भी सामना करती है। यांत्रिक खोज की धारणाओं ने न केवल जानकारी की खोज में क्रांति ला दी है, बल्कि फैंसी ड्राइंग रूम में विश्वकोश को सजावट का सामान भी बना दिया है। वे अब, शायद, इस बात का प्रदर्शन बन गए हैं कि बहुत समय पहले सीखना कैसा हुआ करता था। इन सबका न केवल कक्षा पर बल्कि कार्यस्थल पर भी प्रभाव पड़ता है। इसकी सटीक अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं है, लेकिन हंगामा जारी है। जबकि पहले शिक्षण संस्थाएं इस बात पर बराबर ध्यान देती थीं कि कैसे पढ़ाया जाए। अब फोकस इस बात पर भी बराबर है कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। कक्षा और कार्यस्थल दोनों में दबाव समान रूप से तीव्र है, जो एक आदर्श बदलाव की मांग करता है। शिक्षण संगठनों के लिए वास्तविक चुनौती प्रतिमान परिवर्तन को मूर्त रूप देने में है। स्वयं को यह याद दिलाना उपयोगी होगा कि शिक्षण संगठन कोई नई बात नहीं है। एक प्रस्ताव के रूप में, स्वयं को पुनः अविष्कृत करते रहने की आवश्यकता आम हो गई है। बहुत पहले नहीं, दिमाग को खुला रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। उनमें से अधिकांश अब लगभग एक नए प्रतिमान में बदल गया हैः दिमाग को बढ़ते रहना। कौशल और दक्षताओं को बढ़ाना एक शिक्षण संगठन का एक परिभाषित गुण बना हुआ है। यह बस हैस्वयं को केवल 'दिमाग को खुला रखने' तक ही सीमित रखना संभव नहीं है। आज, सीखने के लिए प्रौद्योगिकी के नए और उभरते पैटर्न की सराहना करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। बहुत पहले नहीं, मशीन के उपयोग के लिए साक्षरता महत्वपूर्ण थी क्योंकि किसी को वर्णमाला का अध्ययन करना पड़ता था। अब स्थिति उस संदर्भ में पहुंच गई है जहां भले ही किसी के पास वर्णमाला को पंच करने की क्षमता न हो, वह मशीन में बोल सकता है और मशीन उसका अनुपालन करेगी। फिलहाल, यह प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में है, लेकिन जिन समस्याओं से निपटना है, वे दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। सीखने के दायरे में बदलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर कोई लिखने में सक्षम हुए बिना भी समस्याओं को हल कर सकता है, तो वास्तव में सीखने के पूरे प्रतिमान में एक क्रांति आ जाएगी। इसलिए, एक शिक्षण संगठन का प्रस्ताव कई मूलभूत सुधारों से गुजर रहा है। 20वीं सदी में एक समय था जब प्रौद्योगिकी ने दूरी की प्रकृति को बदल दिया था, और अब प्रौद्योगिकी के प्रति एक उभरता हुआ दृष्टिकोण प्रतीत होता है जो समय की प्रकृति को ही बदल सकता है। वर्तमान समय और भविष्य का समय तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से एक-दूसरे में विलीन होने के लिए तैयार हैं, जिससे व्यक्ति को टाइम मशीन से गुजरने की अनुमति मिलती है, भले ही अस्थायी रूप से ही सही। ये मौलिक अभिधारणाएं हैं और हम वर्तमान में जो करने में सक्षम हैं, उससे कहीं अधिक गहराई से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार पंजाब को बदनाम करते हैं।

संपादक की कलम से

क्या 2025 के लिए नीट युजी परीक्षा बदल जाएगा?

उम्मीद है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) नीट यूजी 2025 परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित करेगी। 2024 नीट परीक्षा में करीब 24.5 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था. हालाँकि, नीट युजी 2025 के लिए आवेदकों की संख्या बढ़ने की संभावना है, जिससे प्रतिस्पर्धा और भी कठिन हो जाएगी।

नीट युजी 2024 में कदाचार और पेपर लीक के दावों सहित कई विवादों के बाद, छात्र अनिश्चित हैं कि नीट युजी 2025 परीक्षा पैटर्न में बदलाव होंगे या नहीं। इन मुद्दों ने परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। नीचे दिए गए लेख में चर्चा की गई है कि क्या 2025 के लिए एनईईटी परीक्षा पैटर्न बदल जाएगा और एनईईटी उम्मीदवारों की अन्य चिंताओं का समाधान किया जाएगा।

ये चिंताएँ समझ में आती हैं, लेकिन नीट 2025 परीक्षा पैटर्न में बदलाव के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। उम्मीद है कि एनटीए जल्द ही नीट 2025 के लिए सूचना बुलेटिन जारी करेगा, जो स्पष्ट करेगा कि परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव किया जाएगा या नहीं।

नीट 2025 के लिए करो या मरो अध्याय

साथ ही, एनटीए द्वारा जेईई परीक्षा पैटर्न 2025 में किए गए बदलावों के बाद, यह उम्मीद है कि एनईईटी 2025 परीक्षा पैटर्न की अखंडता बनाए रखने के लिए इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। जेईई मेन 2025 के सेक्शन बी में अब वैकल्पिक प्रश्न नहीं होंगे; इसके बजाय, इसमें प्रत्येक विषय के लिए पांच अनिवार्य संख्यात्मक प्रश्न होंगे।

हालांकि एनटीए ने अब तक नीट 2025 परीक्षा पैटर्न में किसी भी संशोधन की घोषणा नहीं की है, लेकिन एजेंसी के लिए एनईईटी उम्मीदवारों के आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए एक पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे नीट युजी 2025 नजदीक आ रहा है, ऐनईटी को छात्रों की चिंताओं को दूर करना चाहिए और परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इसकी अखंडता को बनाए रखना चाहिए।

चूंकि नीट युजी 2025 परीक्षा पैटर्न में बदलाव के संबंध में कोई अपडेट नहीं आया है, इसलिए उम्मीदवारों को मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। नीट युजी 2025 परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी और इसकी अवधि 3 घंटे 20 मिनट होगी। कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी, जिनमें से उम्मीदवारों को 180 का उत्तर देना होगा।

नीट युजी 2025 परीक्षा कुल 720 अंकों की होगी, जिसमें प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में होंगे। अंकन योजना वही रहती हैः उम्मीदवारों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 अंक प्राप्त होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक का नुकसान होगा। नीचे दी गई तालिका नीट युजी 2025 परीक्षा पैटर्न और अंकन योजना पर विवरण प्रदान करती हैः

नीट परीक्षा पैटर्न 2025 और अंकन योजना

क्र.सं. क्रमांक विषय प्रश्नों की संख्या कुल अंक

1 भौतिकी अनुभाग एः 35 + अनुभाग बीः 10 (15 प्रदान किए गए, 10 का उत्तर दिया जाना है) = 45 180

2 रसायन विज्ञान अनुभाग एः 35 + अनुभाग बीः 10 (15 प्रदान किए गए, 10 का उत्तर दिया जाना है) = 45 180

3 प्राणीशास्त्र अनुभाग एः 35 + अनुभाग बीः 10 (15 प्रदान किए गए, 10 का उत्तर दिया जाना है) = 45 180

4 वनस्पति विज्ञान अनुभाग एः 35 + अनुभाग बीः 10 (15 प्रदान किए गए, 10 का उत्तर दिया जाना है) = 45 180

कुल 180 720

क्या नीट युजी 2025 ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा?

नीट युजी 2025 ऑनलाइन आयोजित होने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। नीट युजी 2024 विवाद के बाद निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इस बदलाव पर विचार किया जा रहा है, जिससे परीक्षा प्रक्रिया में विश्वास प्रभावित हुआ।

विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद

राय

असम नागरिकता वैध

असम से जुड़े नागरिकता कानून की धारा 6-ए 'संवैधानिक' है। यह सर्वोच्च अदालत की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से फैसला लिया है। फैसला करीब 12 साल के बाद, 17 याचिकाओं पर, विचार करने के बाद लिया गया है। इस फैसले के बाद 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 की अवधि के दौरान, भारतीय मूल के, जो बांग्लादेशी भारत में आए हैं और यहीं बसे हैं, उन्हें 'भारतीय' नागरिकता मिल जाएगी। हालांकि तारीखों को लेकर भी सवाल हैं कि असम और शेष भारत में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को नियमित करने के लिए अलग-अलग तारीखें तय की गई हैं। ऐसा क्यों किया जाना चाहिए? बहरहाल 25 मार्च, 1971 के बाद असम में आने वाले विदेशियों को 'भारतीय' नागरिकता नहीं मिलेगी। 1970 और 1980 के दशक में असम 'विदेशी घुसपैठ' के मुद्दे पर उबलता रहा, आंदोलन तक छिड़ गए और हिंसा भी हुई। असम भारत के पूर्वोत्तर का सीमावर्ती राज्य है। अपनी संस्कृति, सामाजिक पहचान, विरासत और भाषा को सुरक्षित और संरक्षित रखने के मकसद से असमिया बिरादरी ने खासकर बांग्लादेशी प्रवासियों का विरोध किया। आशंकाएं जताई गईं कि असम की संस्कृति और आबादी के समीकरण तक बदल सकते हैं। मुस्लिम आबादी एक दिन बहुसंख्यक हो सकती है। असमिया लोगों का मताधिकार तक प्रभावित हो सकता है। भारत के संदर्भ में विभाजन के दाग आज भी कच्चे और ताजा हैं।

अवैध प्रवास एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। 1985 में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, असम सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच एक तितरफा समझौता हुआ। प्रवास और प्रवेश की तारीखों को लेकर सहमति बनी और उसके बाद संसद में एक विधेयक पारित कर 'नागरिकता कानून' में नई धारा-6 ए-जोड़ी गई। संविधान पीठ के चार न्यायाधीशों, जिनमें प्रधान न्यायाधीश धनंजय वाई. चंद्रचूड़ भी शामिल थे, ने इस धारा को 'संसदीय विधायी समाधान' माना, लिहाजा धारा 6-ए को 'संवैधानिक' भी माना, लेकिन जस्टिस पारदीवाला का मानना था कि धारा 6-ए राजनीतिक समझौते को कानूनी मान्यता देने के लिए लाई गई थी। इस समझौते का मतलब सिर्फ नागरिकता प्रदान करना नहीं था। दरअसल यह असम के लोगों को शांत करने के लिए था कि ऐसे समावेश से राज्य में होने वाले चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरा मानना है कि धारा 6-ए की वैधता निर्धारित करते समय समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों के मकसद को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

ऐसे में धारा 6-ए समय बीतने के साथ 'असंवैधानिक' हो गई है। जस्टिस सूर्यकांत का मानना है कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि विदेशी प्रवासियों से असमिया संस्कृति, भाषा और सामाजिक पहचान पर कोई गंभीर प्रभाव पड़ा है। हमने यह दलील भी खारिज कर दी है कि 6-ए भेदभावपूर्ण, मनमानी धारा है। 1966 और 1971 की अवधि में आए प्रवासियों के लिए स्पष्ट परिभाषित शर्तें दी गई हैं। बहरहाल असम में इस कानून के लिए विशेष रूप से छात्रों ने छह साल तक प्रदर्शन किए थे। नतीजतन समझौता हुआ और संसद में कानून पारित किया गया। यदि यह व्यवस्था न की जाती, तो शायद बांग्लादेश से प्रवासियों की संख्या न थमती। गंभीर सवाल यह है कि यदि 1971 के बाद आए प्रवासियों को भी स्वीकार कर लिया जाता है, तो उससे क्या होगा? ऐसी उदारता घुसपैठ के लिए उकसा सकती है।

सुविधा असुविधा

विजय गर्ग

शहरों के विस्तार के साथ ही शहरों में डिब्बाबंद खाने और बोतलबंद पेय का चलन तेजी से बढ़ा है। कई बार पैकिंग के डिब्बे ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि इन्हें धोकर रख लेते हैं, आगे कहीं खाना भर कर ले जाने या कोई और छोटा-मोटा सामान रखने के काम आएंगे। यों लालच में हम अपने घर में भी ढेर सारे प्लास्टिक के डिब्बे, बोतलें, छोटे-मोटे गत्ते के डिब्बे, कार्टन और कांच की बोतलें बढ़ाते जाते हैं। धीरे-धीरे रसोईघर की अलमारियों में ये डिब्बे बढ़ते जाते हैं और फिर थोड़े दिनों बाद रसोईघर एक छोटा संग्रहालय की तरह दिखने लगता है। कई बार कुछ लोग खाली भूखंडों में इन्हें फेंकते देखे जा सकते हैं। इन खाली डिब्बों में खाने की गंध से गाय, कुत्ते भोजन की तलाश में आ जाते हैं। इसी क्रम में कई बार गायों के पेट में प्लास्टिक चले जाने के कारण उन्हें गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते देखा जा सकता है। कई बार उनकी मौत तक हो जाती है।

अक्सर प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाते रहे हैं, लेकिन वे 'ऊंट के मुंह में जीरा' जितने ही चल पाए हैं। कूड़े का उचित निपटान आज भी दुनिया के सामने एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जितना उसका उत्पादन होता है, उतने उसके निपटान के प्रयास और साधन आज भी उपलब्ध नहीं हैं। यह दुनिया की एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। वर्ष 2020 में दुनियाभर में 2.20 अरब टन कचरा पैदा हुआ। विश्व बैंक का अनुमान है कि 2050 तक इसका उत्पादन 3.88 अरब टन हो जाएगा। बहुत से स्थानों और शहरों में बड़ी संख्या में कूड़े का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना निपटान का विकल्प देखा जाता रहा है जो स्थायी हल नहीं है। कचरे के संपर्क में आने से बैक्टीरिया जानवरों और मनुष्यों तक आ जाते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं। इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है, जो वन्यजीवों और हमारी अर्थव्यवस्था को खतरे में डालता। धरती की सुंदरता नष्ट होती है। कई देशों में इस समस्या का हल समुद्र में भी ढूंढ़ा गया। समुद्र कूड़ा डाल देना भी कम नुकसानदायक नहीं है। समुद्री कूड़ा नौवहन और जलीय जीवों के लिए घातक है।

कुछ समय पहले आनलाइन खरीदारी के तहत मंगवाई गई एक पुस्तक जब पहुंची, तो पुस्तक पर ध्यान जाने से पहले इस पर ध्यान गया कि उसे एक डिब्बे में बंद करने के लिए क्या- क्या जतन किए गए थे। पुस्तक चौड़ी पारदर्शी टेप से पूरी तरह बंद की गई थी। उसके अंदर एक मोटा कागज था और उसके अंदर फिर प्लास्टिक की एक मोटी 'शीट' थी। पुस्तक को इतने मजबूत तरीके से डिब्बाबंद किया गया था कि उसे बिना चाकू से खोला जाना लगभग नामुमकिन था। सवाल है कि एक किताब को सुरक्षित अपनी जगह पहुंचाने के लिए क्या उसे इतने मजबूत तरीके से डिब्बाबंद करने की जरूरत होती है? आनलाइन खरीदारी में कई ऐसे सामान होते हैं, जिन्हें इसी तरह भेजा जाता है। ऐसे डिब्बाबंद करने में ही कितनी सामग्री लगती होगी? क्या इससे कुछ कम में काम नहीं चल सकता है, जिससे वस्तु सुरक्षित अपनी जगह पहुंच जाए और ज्यादा कचरा भी न पैदा हो?

दरअसल, अब साफ-सफाई की व्यवस्था में अभिन्न हो गई अव्यवस्था की समस्या गांवों, शहरों, देशों से आगे बढ़कर विश्व की समस्या हो गई है और विश्व से देशों, शहरों और गांवों की भी समस्या बनती जा रही है। लगभग पच्चीस से तीस साल पुराने कूड़े से एक प्रकार का द्रव्य 'लीचेट' निकलना शुरू हो जाता है। यह जहरीला होता है। यह कूड़े के पहाड़ों के आसपास के भूजल और मिट्टी में मिलकर उसे जहरीला बना देता है। कूड़े के ढेरों से उठने वाली बदबू और आए दिन उन्हें जलाने से उठने वाला धुंआ, दोनों ही वहां रहने वालों के लिए कष्टदायक हैं। हमारे देश में कचरा निस्तारण की समस्या को लेकर लगातार दायर की जाने वाली याचिकाओं के बाद अब सूखा कचरा निष्पादन नियम 2016 लाया गया है। इन नियमों में सूखे और गीले कूड़े को अलग-अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने की स्थिति में दंड का प्रावधान भी रखा गया है।

संविधान के अनुच्छेद 51 (ए) में दिए गए मौलिक कर्तव्यों में स्पष्ट कहा गया है कि 'जंगल, झील, नदी और वन्य-जीवन जैसे प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और विकास करना हर नागरिक का कर्तव्य है।' कचरा निष्पादन के संबंध में कुछ अन्य नियम ऐसे हैं जो कचरे का जैविक निष्पादन कर उसे संतुलित रखने पर बल देते हैं। इससे संबंधित बहुत-चुनौतियां अभी भी सामने खड़ी हैं, जिनसे निपटने के लिए कानूनों के व्यावहारिक स्तर पर अमल किए जाने की नितांत आवश्यकता है। कई स्थानों पर लगाए गए कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र भी कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। इन संयंत्रों से आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। इनमें आने वाला गीला कूड़ा व्यर्थ जाता है। केवल सूखा कूड़ा ही ऊर्जा उत्पादन के काम आता है। दूसरे, इन संयंत्रों से अपेक्षित ऊर्जा भी नहीं मिल रही है। कचरा रूपांतरण संयंत्रों से वायु प्रदूषण बहुत अधिक होता है। इस बड़ी समस्या के हल बड़े और छोटे स्तरों पर करने की जरूरत है या यों कहें कि इस ओर कोशिशें तेज करने की महती आवश्यकता है।

विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

हमें लगता है कि इन्हें धोकर रख लेते हैं, आगे कहीं खाना भर कर ले जाने या कोई और छोटा-मोटा सामान रखने के काम आएंगे। यों लालच में हम अपने घर में भी ढेर सारे प्लास्टिक के डिब्बे, बोतलें, छोटे-मोटे गत्ते के डिब्बे,

evian
FIJI
Liquid Death
essence
GLACEAU smartwater
DASANI
flow

कार्टन और कांच की बोतलें बढ़ाते जाते हैं। धीरे-धीरे रसोईघर की अलमारियों में ये डिब्बे बढ़ते जाते हैं और फिर थोड़े दिनों बाद रसोईघर एक छोटा संग्रहालय की तरह दिखने लगता है। कई बार कुछ लोग खाली भूखंडों में इन्हें फेंकते देखे जा सकते हैं। इन खाली डिब्बों में खाने की गंध से गाय, कुत्ते भोजन की तलाश में आ जाते हैं। इसी क्रम में कई बार गायों के पेट में प्लास्टिक चले जाने के कारण उन्हें गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते देखा जा सकता है। कई बार उनकी मौत तक हो जाती है।

अक्सर प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाते रहे हैं, लेकिन वे 'ऊंट के मुंह में जीरा' जितने ही चल पाए हैं। कूड़े का उचित निपटान आज भी दुनिया के सामने एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जितना उसका उत्पादन होता है, उतने उसके निपटान के प्रयास और साधन आज भी उपलब्ध नहीं हैं। यह दुनिया की एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। वर्ष 2020 में दुनियाभर में 2.20 अरब टन कचरा पैदा हुआ। विश्व बैंक का अनुमान है कि 2050 तक इसका उत्पादन 3.88 अरब टन हो जाएगा। बहुत से स्थानों और शहरों में बड़ी संख्या में कूड़े का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना निपटान का विकल्प देखा जाता रहा है जो स्थायी हल नहीं है। कचरे के संपर्क में आने से बैक्टीरिया जानवरों और मनुष्यों तक आ जाते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं। इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है, जो वन्यजीवों और हमारी अर्थव्यवस्था को खतरे में डालता। धरती की सुंदरता नष्ट होती है। कई देशों में इस समस्या का हल समुद्र में भी ढूंढ़ा गया। समुद्र कूड़ा डाल देना भी कम नुकसानदायक नहीं है। समुद्री कूड़ा नौवहन और जलीय जीवों के लिए घातक है।

कुछ समय पहले आनलाइन खरीदारी के तहत मंगवाई गई एक पुस्तक जब पहुंची, तो पुस्तक पर ध्यान जाने से पहले इस पर ध्यान गया कि उसे एक डिब्बे में बंद करने के लिए क्या- क्या जतन किए गए थे। पुस्तक चौड़ी पारदर्शी टेप से पूरी तरह बंद की गई थी। उसके अंदर एक मोटा कागज था और उसके अंदर फिर प्लास्टिक की एक मोटी 'शीट' थी। पुस्तक को इतने मजबूत तरीके से डिब्बाबंद किया गया था कि उसे बिना चाकू से खोला जाना लगभग नामुमकिन था। सवाल है कि एक किताब को सुरक्षित अपनी जगह पहुंचाने के लिए क्या उसे इतने मजबूत तरीके से डिब्बाबंद करने की जरूरत होती है? आनलाइन खरीदारी में कई ऐसे सामान होते हैं, जिन्हें इसी तरह भेजा जाता है। ऐसे डिब्बाबंद करने में ही कितनी सामग्री लगती होगी? क्या इससे कुछ कम में काम नहीं चल सकता है, जिससे वस्तु सुरक्षित अपनी जगह पहुंच जाए और ज्यादा कचरा भी न पैदा हो?

दरअसल, अब साफ-सफाई की व्यवस्था में अभिन्न हो गई अव्यवस्था की समस्या गांवों, शहरों, देशों से आगे बढ़कर विश्व की समस्या हो गई है और विश्व से देशों, शहरों और गांवों की भी समस्या बनती जा रही है। लगभग पच्चीस से तीस साल पुराने कूड़े से एक प्रकार का द्रव्य 'लीचेट' निकलना शुरू हो जाता है। यह जहरीला होता है। यह कूड़े के पहाड़ों के आसपास के भूजल और मिट्टी में मिलकर उसे जहरीला बना देता है। कूड़े के ढेरों से उठने वाली बदबू और आए दिन उन्हें जलाने से उठने वाला धुंआ, दोनों ही वहां रहने वालों के लिए कष्टदायक हैं। हमारे देश में कचरा निस्तारण की समस्या को लेकर लगातार दायर की जाने वाली याचिकाओं के बाद अब सूखा कचरा निष्पादन नियम 2016 लाया गया है। इन नियमों में सूखे और गीले कूड़े को अलग-अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने की स्थिति में दंड का प्रावधान भी रखा गया है।

संविधान के अनुच्छेद 51 (ए) में दिए गए मौलिक कर्तव्यों में स्पष्ट कहा गया है कि 'जंगल, झील, नदी और वन्य-जीवन जैसे प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और विकास करना हर नागरिक का कर्तव्य है।' कचरा निष्पादन के संबंध में कुछ अन्य नियम ऐसे हैं जो कचरे का जैविक निष्पादन कर उसे संतुलित रखने पर बल देते हैं। इससे संबंधित बहुत- चुनौतियां अभी भी सामने खड़ी हैं, जिनसे निपटने के लिए कानूनों के व्यावहारिक स्तर पर अमल किए जाने की नितांत आवश्यकता है। कई स्थानों पर लगाए गए कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र भी कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। इन संयंत्रों से आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। इनमें आने वाला गीला कूड़ा व्यर्थ जाता है। केवल सूखा कूड़ा ही ऊर्जा उत्पादन के काम आता है। दूसरे, इन संयंत्रों से अपेक्षित ऊर्जा भी नहीं मिल रही है। कचरा रूपांतरण संयंत्रों से वायु प्रदूषण बहुत अधिक होता है। इस बड़ी समस्या के हल बड़े और छोटे स्तरों पर करने की जरूरत है या यों कहें कि इस ओर कोशिशें तेज करने की महती आवश्यकता है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

दूसरी तिमाही के साथ कई फैक्टर्स रहेंगे अहम

कल से शुरू होने वाले हफ्ते में ये ट्रिगर्स रहेंगे अहम

परिवहन विशेष न्यूज

शेयर बाजार के निवेशकों को मालूम होना चाहिए कि आने वाले हफ्ते में बाजार की चाल को कौन-से फैक्टर्स प्रभावित करेंगे। इसके अलावा बाजार आगामी हफ्ते में बाजार के ट्रिगर्स क्या है। बता दें कि वैश्विक भू-राजनीतिक और घरेलू राजनीतिक उथल-पुथल बाजार की चाल को प्रभावित करते हैं। आइए जानते हैं कि इस हफ्ते बाजार के लिए कौन-से फैक्टर्स जरूरी रहेंगे।

कैसी रहेगी
बाजार की चाल

नई दिल्ली। कल से अक्टूबर का नया कारोबारी हफ्ता शुरू हो जाएगा। इस हफ्ते शेयर बाजार की चाल को कई फैक्टर्स निर्धारित करेंगे। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि आगामी हफ्ते में बाजार की चाल को कौन-से फैक्टर्स तय करेंगे।

ये फैक्टर्स रहेंगे अहम

शेयर बाजार के एनलिस्ट के अनुसार आगामी हफ्ते में कंपनियों द्वारा जारी दूसरी तिमाही के नतीजों का असर बाजार की चाल पर पड़ेगा। इसके अलावा वैश्विक बाजार से आ रहे संकेत और विदेशी निवेशकों की चाल भी बाजार के सेंटीमेंट को प्रभावित करेगी। विशषज्ञों का मानना है कि इस हफ्ते शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा।

शेयर बाजार के निवेशकों को कंपनी द्वारा जारी होने वाले तिमाही नतीजों पर नजर बनाए रखनी चाहिए। कंपनी तिमाही नतीजे में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जानकारी देगी। हालांकि, इजरायल और ईरान में चल रही भू-राजनीतिक चिंताओं का प्रभाव भी बाजार पर पड़ेगा।

प्रवेश गौड़, वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक, स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड

इसके अलावा अगर क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा होता है तो वह भी मार्केट को प्रभावित कर सकता है। विदेशी निवेशकों की ट्रेडिंग भी बाजार की परफॉर्मेंस को प्रभावित करेगी। ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन और घरेली राजनीतिक चाल भी बाजार के अहम फैक्टर्स रहेंगे।

एचडीएफसी बैंक की तिमाही नतीजा (HDFC Bank Q2 Result)

देश के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने शनिवार को दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किये थे। इस नतीजों का असर सोमवार को शेयर पर देखने को मिल सकता है। एचडीएफसी बैंक ने बताया कि जुलाई से सितंबर महीने में बैंक का नेट प्रॉफिट 6 फीसदी बढ़कर 17,825.91 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, बैंक का पोस्ट-टैक्स नेट ग्रो 16,820.97 करोड़ रुपये हो गया।

ये कंपनी जारी करेंगे तिमाही नतीजे

आगामी हफ्ते में आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बीपीसीएल, एचपीसीएल और अल्ट्राटेक तिमाही नतीजे जारी करेंगे। इसके अलावा बजाज हाउसिंग फाइनेंस, अदाणी ग्रीन एनर्जी, बजाज फाइनेंस, पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन-कम्यूनिकेशन, जोमैटो, बजाज फिनजर्व और बैंक ऑफ बड़ौदा भी तिमाही नतीजे जारी करेगा। निवेशकों को इन कंपनियों के शेयर पर भी नजर बनाए रखनी होगी।

इस हफ्ते शनिवार को एचडीएफसी बैंक के साथ कोटक महिंद्रा बैंक ने भी तिमाही नतीजे जारी किये थे।

कोटक महिंद्रा बैंक तिमाही नतीजा

कोटक महिंद्रा बैंक ने शनिवार को तिमाही नतीजे जारी किये थे। बैंक ने बताया कि सितंबर तिमाही में उसका ग्रोथ 13 फीसदी बढ़कर 5,044 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं बैंक का नेट प्रॉफिट 5 फीसदी बढ़कर 3,344 करोड़ रुपये हो गया।

रिलायंस कब देगी बोनस शेयर, क्या दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ होगा एलान?

परिवहन विशेष न्यूज

मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज सोमवार को जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजों का एलान करेगी। इससे रिलायंस के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। इससे पहले रिलायंस ने 11 के अनुपात में बोनस शेयर का भी एलान किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बोनस शेयर इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेटा का एलान भी 14 अक्टूबर को ही किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि बोनस शेयर की पूरी डिटेल।

नई दिल्ली। अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) सोमवार (14 अक्टूबर) को दूसरी तिमाही के नतीजों का एलान करेगी। रिलायंस ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बोर्ड 14 अक्टूबर को मीटिंग करेगा। इसमें वह जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही और अप्रैल-सितंबर 2024 छमाही के फाइनेंशियल रिजल्ट पर मुहर लगाएगा।

मुकेश अंबानी की RIL फिलहाल देश की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी है। बीएसई के डेटा के मुताबिक, रिलायंस का मार्केट कैप 18.55 लाख करोड़ रुपये है। इसके शेयर शुक्रवार (11 अक्टूबर) को बीएसई पर 2742.20 रुपये के भाव पर बंद हुए थे। कंपनी में जून 2024 के आखिर तक प्रमोटरों के पास 50.33 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। वहीं, FII के पास 21.75 फीसदी और DII के पास 17.30 फीसदी स्टेक था।

बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट अभी घोषित नहीं

रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ने 5 सितंबर को सालाना आम बैठक से पहले 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसक मतलब कि शेयरहोल्डर्स को प्रत्येक शेयर पर एक शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। रिलायंस ने अभी तक बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का एलान नहीं किया है। माना जा रहा है कि इसका एलान भी 14 अक्टूबर को ही हो सकता है।

रिकॉर्ड डेट तक जिन लोगों के पास रिलायंस के शेयर होंगे यानी उनके नाम शेयरों के लाभार्थी मालिकों के तौर पर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी या डिपॉजिटरीज के रिकॉर्ड्स में होंगे। उन्हें बोनस बोनस शेयर मिलेगा। मुकेश अंबानी की रिलायंस 7 साल बाद बोनस शेयर देगी। इससे पहले कंपनी ने 2017 में भी 1:1 के रेशियो में शेयरधारकों को बोनस शेयर दिया था। रिलायंस ने साल 2009 में भी इसी अनुपात में बोनस शेयर दिया था।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों का हाल

रिलायंस के शेयरों में पिछले कुछ समय से सुस्ती देखने को मिल रही है। शुक्रवार को रिलायंस के शेयर 0.25 फीसदी तेजी के साथ 2,749.00 रुपये पर बंद हुए थे। लेकिन, पिछले एक महीने के दौरान रिलायंस के शेयरों में 6.66 फीसदी की गिरावट आई है। पिछले 6 महीने का आंकड़ा देखें, तो भी निवेशकों को रिलायंस से 6.17 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न मिला है। हालांकि, पिछले एक साल में रिलायंस के शेयरों में 17 फीसदी से अधिक का उछाल आया है।

शेयर बाजार के जानकारों का मानना है कि बोनस शेयर इश्यू और पश्चिमी एशिया में भूराजनीतिक तनाव घटने के साथ रिलायंस के शेयरों में तेजी आ सकती है। अगर दूसरी तिमाही में रिलायंस के नतीजे बेहतर रहते हैं, तो इसका असर भी कंपनी के शेयरों पर दिखेगा।

क्या जॉब के साथ-साथ मिलती है पेंशन, जान लीजिए क्या कहता है ईपीएफओ के नियम

रिटायरमेंट के बाद मोटा फंड जमा हो सके इसके लिए ईपीएफओ काफी अच्छी स्कीम है। इस स्कीम में जहां रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त राशि मिलती है तो दूसरी तरफ पेंशन का लाभ भी मिलता है। ऐसे में कई ईपीएफओ मेंबर्स के मन में सवाल आता है कि क्या ईपीएस स्कीम में जॉब के साथ-साथ पेंशन का लाभ मिल सकता है। आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं।

नई दिल्ली। रिटायरमेंट के बाद फंड और पेंशन का लाभ कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में मिलता है। इस स्कीम का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा किया जाता है। ईपीएस स्कीम में कर्मचारी हर महीने अपनी सैलरी का फिक्सड अमाउंट निवेश करते हैं। कर्मचारी के साथ कंपनी द्वारा भी योगदान किया जाता है।

यह स्कीम रिटायरमेंट के बाद मैच्योर हो जाता है। जब स्कीम मैच्योर होती है तो फंड का एक हिस्सा एकमुश्त मिलता है बाकी पेंशन के तौर पर मासिक दिया जाता है। वैसे तो कई लोगों को ईपीएस के पेंशन का लाभ रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है। लेकिन, कई कर्मचारी इस बात से अनजान है कि ईपीएस स्कीम में जॉब के साथ-साथ भी पेंशन का लाभ मिलता है। हम आपको इसी के बारे में बताएंगे।

हर महीने कितने करना होता है योगदान

कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा ईपीएफओ में देता है। इस 12 फीसदी में से 8.3 फीसदी पीएफ अकाउंट (PF Account) में जमा होता है और बाकी 3.67 फीसदी ईपीएस स्कीम में जमा होता है। ईपीएस में जमा राशि ही मैच्योर होने के बाद पेंशन के तौर पर दी जाती है।

जॉब के साथ कब मिलती है पेंशन

ईपीएफओ के नियम (EPFO Rule) के अनुसार ईपीएस पेंशन का लाभ कर्मचारी को तब मिलता है जब वह लगातार 10 साल तक निवेश करते हैं। इसके अलावा जब कर्मचारी की आयु 50 साल से ज्यादा हो जाती है तो वह पेंशन के लिए क्लेम कर सकता है। अगर कर्मचारी ने 10 साल तक ईपीएस स्कीम में योगदान दिया पर उसकी आयु 50 साल से कम है तो वह पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकता है।

अर्ली पेंशन में कम मिलती है पेंशन

अगर कर्मचारी की आयु 50 से 58 साल के बीच की है और वह रिटायरमेंट से पहले पेंशन क्लेम करता है तो उसे पेंशन की राशि कम मिलेगी। दरअसल, ईपीएफओ के नियम के अनुसार अर्ली पेंशन में हर साल 4 फीसदी की कटौती होती है।

इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी व्यक्ति की आयु 52 है और वह अर्ली पेंशन के लिए क्लेम करता है तो उसे अभी पेंशन अमाउंट में से केवल 76 फीसदी ही मिलेगा। इसकी वजह है कि पेंशन प्राप्त करने की आयु 58 साल है और वह 6 साल पहले ही पेंशन के लिए क्लेम कर रहा है। ऐसे में 4 फीसदी सालाना दर के हिसाब से 6 साल में पेंशन अमाउंट में 24 फीसदी की कटौती होगी।

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बीच चार कंपनियों का बढ़ गया एम-कैप, ICICI और HDFC Bank रहा टॉप गेनर

परिवहन विशेष न्यूज

पिछले हफ्ते शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव भरा कारोबार रहा। इस उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बीच ICICI और HDFC Bank के एम-कैप में शानदार तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा शेयर बाजार के टॉप-10 कंपनियों में से दो के एम-कैप भी बढ़े हैं। वहीं 6 कंपनियों के एम-कैप में गिरावट आई है। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि किस कंपनी के एम-कैप में कितनी बढ़त हुई है।

नई दिल्ली। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव भरा कारोबार था। वैश्विक बाजार से मिल रहे कमजोर संकेतों और विदेशी निवेशकों द्वारा हो रही निकासी के कारण बाजार लाल निशान पर कारोबार कर रहा था। इस उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के कारण कई कंपनियों के मार्केट-कैपिटलाइजेशन में गिरावट आई है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार पिछले हफ्ते बाजार के टॉप-10 फर्म में से 4 फर्मों के एम-कैप में संयुक्त रूप से 81,151 करोड़ रुपये बढ़े हैं। इनमें से सबसे ज्यादा गेनर आईसीआईसी बैंक (ICICI Bank) और एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) रहे।

वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का बाजार मूल्यांकन गिर गया। इन कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में संयुक्त रूप से 76,622.05 करोड़ रुपये गिरावट हुई।

इनका बढ़ा एम-कैप

आईसीआईसीआई बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन में 28,495.14 करोड़ रुपये जुड़ गए। इसके बाद कंपनी का एम-कैप 8,90,191.38 करोड़ रुपये हो गया।

एचडीएफसी बैंक का बाजार मूल्यांकन 23,579.11 करोड़ रुपये बढ़कर 12,82,848.30 करोड़ रुपये हो गया।

भारतीय स्टेट बैंक का एम-कैप 17,804.61 करोड़ रुपये की बढ़त के साथ 7,31,773.56 करोड़ रुपये हो गया।

भारती एयरटेल का बाजार पूंजीकरण 11,272.45 करोड़ रुपये बढ़कर 9,71,707.61 करोड़ रुपये हो गया।

इन कंपनियों के एम-कैप में आई गिरावट

जहां एक तरफ बाजार के टॉप-4 फर्म के एम-कैप में इजाफा हुआ है तो दूसरी तरफ टॉप-10 फर्म में से 6 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में गिरावट आई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार-

इंफोसिस का एमकैप 23,314.31 करोड़ रुपये घटकर 7,80,126.10 करोड़ रुपये रह गया।

रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्यांकन 16,645.39 करोड़ रुपये घटकर 18,38,721.14 करोड़ रुपये रह गया।

हिंदुस्तान यूनिलीवर का एमकैप 15,248.85 करोड़ रुपये घटकर 6,38,066.75 करोड़ रुपये हो गया।

टीसीएस का एमकैप 10,402.01 करोड़ रुपये गिरकर 14,91,321.40 करोड़ रुपये रह गया।

एलआईसी का मूल्यांकन 8,760.12 करोड़ रुपये कम होकर 5,91,418.91 करोड़ रुपये हो गया।

आईटीसी का एमकैप 2,251.37 करोड़ रुपये घटकर 6,08,682.29 करोड़ रुपये रह गया।

टॉप-10 फर्म की रैंकिंग

शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के एम-कैप के लिहाज से अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पर है। इसके बाद टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस, भारतीय स्टेट बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी और एलआईसी हैं।

आम जनता पर पड़ सकती है महंगाई की मार, बढ़ सकते हैं सीएनजी के दाम

परिवहन विशेष न्यूज

अगर आपके पास भी सीएनजी व्हीकल है तो इस फेस्टिव सीजन आप पर महंगाई की मार पड़ सकती है। दरअसल माना जा रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जल्द ही सीएनजी की कीमतों को बढ़ाने वाली है। हालांकि अभी तक इस पर कोई अधिकारिक जानकारी नहीं आई। इस आर्टिकल में जानते हैं कि सीएनजी की कीमतों में कितना इजाफा हो सकता है।

महंगी हो सकती है
CNG

नई दिल्ली। आम जनता महंगाई की मार से पहले ही जूझ रहा है। ऐसे में अब महंगाई को लेकर एक नया अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल, न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि देश की मुख्य ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ सरकार सीएनजी की कीमतों में इजाफा (CNG Price Hike) करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि, इस पर अभी तक कोई अधिकारिक घोषणा नहीं हुई।

कितना महंगा होगा सीएनजी

सरकार ने शहरी रिटेलर के लिए नैचुरल गैस की सप्लाई में 20 फीसदी की कटौती की है। इस कटौती का असर तेल की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि इस कटौती के कारण सीएनजी के दामों में 4 से 6 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार सरकार ने फ्यूल प्राइस पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में भी कटौती की है।

कम हो रही है सप्लाई

सीएनजी की कीमत सरकार तय करती है। पिछले कुछ समय से सीएनजी की सप्लाई कम हो रही है जिसके कारण शहरी गैस खुदरा विक्रेताओं के पास भी कम सप्लाई आ रहा है। कहा जा रहा है कि प्राकृतिक गैस के सप्लाई में सालाना 5 फीसदी की गिरावट आ रही है। सप्लाई में आ रही गिरावट की वजह से सीएनजी के दामों में कमी आ रही है।

क्यों बढ़ेंगे सीएनजी के दाम

घरों के पाइप से मिलने वाली रसोई गैस के इनपुट में कोई बदलाव नहीं आया है। इनकी कीमतों को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर सीएनजी की कीमतों में क्यों बढ़ोतरी होगी? इसका जवाब है कि सीएनजी की मांग मई 2023 की तुलना में काफी कम हो गई है। जहां मई 2023 में सीएनजी की मांग 90 फीसदी थी वो इस महीने 16 अक्टूबर 2024 को गिरकर 50.75 फीसदी हो गई। वहीं, पिछले महीने सितंबर में सीएनजी की मांग 67.74 फीसदी थी।

ऐसे में मांग और सप्लाई में कमी आने के कारण तेल कंपनियों को नैचुरल गैस इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। इस कारण भी सीएनजी 4 से 6 रुपये प्रति किलोग्राम महंगा हो सकता है। सूत्रों के अनुसार अभी तक तेल कंपनियों ने सीएनजी की कीमतों में इजाफा करने की मांग नहीं की है। तेल कंपनियां और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय नैचुरल गैस की मांग और सप्लाई में गिरावट के लिए समाधान ढूंढ रहे हैं।

आईजीएल ने एक फाइलिंग में कहा कंपनी को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य (वर्तमान में 6.5 अमेरिकी डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट) पर सीएनजी बिक्री मात्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए घरेलू गैस आवंटन मिलता है। गेल इंडिया लिमिटेड (घरेलू गैस आवंटन के लिए नोडल एजेंसी) से कंपनी द्वारा प्राप्त संचार के आधार पर सूचित किया कि 16 अक्टूबर 2024 से घरेलू गैस आवंटन में बड़ी कटौती की गई है।

गोल्ड खरीदने और बेचने पर लगता है टैक्स, साथ ही देने होते हैं कई चार्ज

भारत में गोल्ड को शुभ के साथ ही निवेश का काफी अच्छा ऑप्शन माना जाता है। निवेशक गोल्ड में निवेश करना काफी पसंद करते हैं। ऐसे में फेस्टिव सीजन के शुरू होने के साथ ही गोल्ड की डिमांड भी बढ़ जाती है। अगर आप भी गोल्ड खरीदने या बेचने वाले हैं तो बता दें कि सुनार आपसे कई तरह के टैक्स और चार्जिस लेता है।

नई दिल्ली। फेस्टिवल सीजन के शुरुआत के साथ ही सोने की मांग भी बढ़ जाती है। दरअसल, भारत में सोना खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन सोना खरीदना काफी शुभ माना जाता है। अगर आप भी गोल्ड खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए हैं।

हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि सोना खरीदने पर कौन-से टैक्स लगते हैं। इसी के साथ ज्वैलर्स कितने तरह के चार्ज लगाता है। यह सब जानकारी जान लेने के बाद ही आपको गोल्ड खरीदना चाहिए।

लगते हैं ये टैक्स और चार्जिस

कस्टम ड्यूटी

भारत में गोल्ड की मांग को पूरा करने के लिए इसे इम्पोर्ट किया जाता है। ऐसे में इस पर कस्टम ड्यूटी (Custom Duty) लगती है। पहले गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी 12.5 फीसदी थी, जिसे अब भारत सरकार ने कम करके 10 फीसदी कर दी है।

GST

सोने के किसी भी आभूषण को खरीदने पर जीएसटी देना होता है। कस्टमर गोल्ड ज्वैलरी पर 3 फीसदी का टैक्स लगाता है। वहीं, सरकार के साथ AIDC भी 5 फीसदी की दर से टैक्स लगाता है। इसके अलावा मेकिंग चार्ज पर भी जीएसटी का भुगतान करना होता है।

टीडीएस

अगर आप 1 लाख रुपये से ज्यादा का गोल्ड खरीदते हैं तो आपको 1 फीसदी की दर से टीडीएस (TDS) देना होता है।

नोटः यह सभी टैक्स फिजिकल गोल्ड पर लगता है। अगर आप डिजिटल गोल्ड यानी ईटीएफ और बॉन्ड में निवेश करते हैं तो उस पर टैक्स और चार्जिस अलग लगते हैं।

क्या गोल्ड बेचने पर भी लगता है टैक्स

फिजिकल गोल्ड की खरीद के साथ उसके बेचने पर भी टैक्स का भुगतान करना होता है। यह टैक्स इस बात पर निर्भर करता है कि आप गोल्ड कितने साल के बाद बेच रहे हैं। अगर आप गोल्ड तीन साल के भीतर बेच रहे हैं तो इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) लगता है। वहीं, लंबे समय के बाद गोल्ड बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) जो कि 20 फीसदी है वो लगता है। इसके अलावा गोल्ड बेचने पर भी जीएसटी लगती है।

क्या है गोल्ड प्राइस (What is Gold Price?)

फेस्टिव सीजन में गोल्ड की कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 7741 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 7555 रुपये प्रति ग्राम है।

बांग्लादेश के आंतरिक हालात पर है भारत की नजर, मौजूदा युनूस सरकार की विदेश नीति और सुरक्षा व्यवस्था चिंता का विषय

परिवहन विशेष न्यूज

बांग्लादेश के मौजूदा आतंरिक हालात उलझे हुए हैं और राजनीतिक पार्टियों का उहा-पोह भी साफ दिखाई दे रहा है। भारत के कूटनीतिक रणनीतिकार मान रहे हैं कि अभी इंतजार करने की नीति ही सर्वश्रेष्ठ है लेकिन उन्हें इस बात का पक्का भरोसा है कि वहां के भावी राजनीतिक घटनाक्रम में भारत के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। भारत बांग्लादेश के हालात पर पैनी नजर बनाये हुए है।

नई दिल्ली। पड़ोसी देश बांग्लादेश से पूर्व पीएम शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किये हुए ढ़ाई महीने हो गये हैं लेकिन वहां की अंतरिम सरकार अभी तक दीर्घकालिक प्रशासन का कोई रोडमैप नहीं दे पाई है। बांग्लादेश के मौजूदा आतंरिक हालात उलझे हुए हैं और राजनीतिक पार्टियों का उहा-पोह भी साफ दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद भारत नाउम्मीद नहीं है।

भारत के कूटनीतिक रणनीतिकार मान रहे हैं कि अभी इंतजार करने की नीति ही सर्वश्रेष्ठ है लेकिन उन्हें इस बात का पक्का भरोसा है कि वहां के भावी राजनीतिक घटनाक्रम में भारत के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही भारत बांग्लादेश के हालात पर पैनी नजर बनाये हुए है।

बांग्लादेश की केंद्र सरकार का सारा काम अस्थाई तौर पर हो रहा

सूत्रों का कहना है कि बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति में पिछले दो महीने में कोई बदलाव नहीं आया है। राजनीतिक अस्पष्टता पहले की तरह ही है। प्रोफेसर मोहम्मद युनूस की अगुवाई अंतरिम सरकार की तरफ से चुनाव कराने या प्रशासन का कोई रोडमैप नहीं दिया गया है। मौजूदा पुलिस, चुनावी व्यवस्था आदि में बदलाव के लिए समितियां गठित की गई हैं। जबकि संविधान में भी संशोधन करने के लिए अलग से समिति गठित करने पर विचार हो रहा है। बांग्लादेश की केंद्र सरकार का सारा काम अस्थाई तौर पर हो रहा है।

कैबिनेट से दो मंत्रियों को हटाने की मांग

सरकार की आर्थिक नीति, विदेश नीति या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नीति सामने नहीं आ पाई है। पूर्व विपक्षी नेता बेगम खालिदा जिया की राजनीतिक पार्टी बीएनपी के भीतर भी इसको लेकर बेचैनी है। इसी हफ्ते बीएनपी के सदस्यों ने प्रो. युनूस से मुलाकात कर उनसे आगामी चुनाव पर स्थिति स्पष्ट करने और अपने कैबिनेट से दो मंत्रियों को हटाने की मांग की है।

यह विडियो भी देखें

इनकी तरफ से कुछ न्यायधीशों को हटाने व ब्यूरोक्रेसी से भी लोगों को निलंबित करने की मांग की गई है। उक्त सूत्रों के मुताबिक यह बता रहा है कि प्रोफेसर युनूस के साथ बीएनपी के रिश्ते बहुत मधुर नहीं है। दूसरी तरफ, पूर्व पीएम हसीना को सत्ता से बाहर करने में अहम भूमिका निभाने वाले जमाते-इस्लामी की तरफ से भी अंतिरम सरकार पर दबाव बनाने का दबाव है।

जल्द हों चुनाव

यह बताया जा रहा है कि जमात के लोग अंतरिम सरकार की जगह जल्द से जल्द निर्वाचित सरकार के गठन के पक्ष में है। पिछले दिनों अंतरिम सरकार के साथ बैठक में बीएनपी और जमात दोनों की तरफ से जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग रखी गई है। जबकि अंतरिम सरकार का तर्क है कि जब तक हर स्तर पर सुधारों का एजेंडा लागू नहीं किया जाता, तब तक चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है।

वैसे यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि अंतरिम सरकार ने आवामी लीग (पूर्व पीएम हसीना की पार्टी) और पूर्व पीएम हसीना की सरकार में शामिल दूसरे राजनीतिक दलों को विमर्श के लिए नहीं बुलाया है। कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि जिस तरह की स्थिति बन रही है उससे लगता है कि पड़ोसी देश में राजनीतिक अस्थिरता काफी लंबे समय तक चल सकती है।

बीमार व्यक्तियों को भी समय पर वीजा देने में समस्या आ रही

उधर, भारतीय उच्चायोग की गतिविधियां बहुत ही सीमित है। सुरक्षा दृष्टिकोण से भारत ने वहां से अपने काफी सारे राजनयिकों को वापस बुला लिया है जिससे वीजा देने संबंधी प्रक्रिया भी काफी सीमित हो गई है। मांग के मुताबिक बीमार व्यक्तियों को भी समय पर वीजा देने में समस्या आ रही है। जब तक अंतरिम सरकार सुरक्षा प्रबंध को चाक-चौबंद नहीं करेगी, भारत के लिए सामान्य वीजा सेवा देना मुश्किल है।

जाति जनगणना हुई तो गिनी जाएंगी मुसलमानों की भी जातियां, 2025 में हो सकती है जनगणना

केरल के पलक्कड़ में हुई आनुसंगिक संगठनों की बैठक के बाद आरएसएस ने साफ कर दिया था कि वह जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है लेकिन इसका इस्तेमाल राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर समाज को बांटने के लिए जातीय जनगणना का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया था।

नई दिल्ली: जातीय जनगणना होनी की स्थिति में पहली बार देश में मुसलमानों की भी जातियां गिनी जाएगी। भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त इसके लिए जरूरी तैयारी में जुट गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसी महीने महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुसलमानों में जातियों की जनगणना के मुद्दे पर चुप्पी को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया था।

जनगणना 2025 में हो सकती है

प्रधानमंत्री मोदी के बयान को हिंदुओं की तरह मुसलमानों में भी जातियों की जनगणना कराये जाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि कोरोना महामारी और फिर लोकसभा चुनावों के कारण अटकी हुई 2021 की जनगणना 2025 में हो सकेगी।

केंद्र सरकार जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराने को लेकर फैसला नहीं किया है। लेकिन विपक्ष की ओर से जातीय जनगणना के लिए बढ़ते दबाव और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश को देखते हुए मोदी सरकार इसे कराने का फैसला ले सकती है। भाजपा और केंद्र सरकार दोनों की ओर बार-बार साफ किया जा चुका है कि वह जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है।

भारतीय मुसलमान भी कई जातियों में बंटे हुए हैं

पीएम मोदी ने पहले ही साफ कर दिया था कि सिर्फ हिंदुओं को विभाजित करने के लिए जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया जाता है, जबकि हिंदुओं की तरह भारतीय मुसलमान भी कई जातियों में बंटे हुए हैं। वैसे असम में हिमंत बिस्व सरमा की भाजपा सरकार पहले ही मुसलमानों की जातीय जनगणना करा चुकी है।

- हर 10 साल पर भारत में जनगणना कराने वाले महापंजीयक और जनगणना आयुक्त जातीय जनगणना होने की स्थिति में उसके लिए जरूरी तैयारियों में जुट गई है।
- भारत में यह पहली जनगणना होगी, जिसमें सभी आंकड़े डिजिटल जुटाए जाएंगे। इसके लिए तैयार पोर्टल में जातीय जनगणना के आंकड़ों के लिए भी प्रविधान किये जा रहे हैं।

2011 में 86.80 लाख से अधिक जातियां दर्ज

ध्यान देने की बात है कि पिछली बार 2011 में जनगणना के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना के आंकड़े जुटाए गए थे। लेकिन 1931 में हुई जातीय जनगणना में 4,147 जातियों के मुकाबले 2011 में 86.80 लाख से अधिक जातियां दर्ज की गई। जातियों में इस अप्रत्याशित बढ़ोतरी और अन्य अनियमितताओं के कारण पहले मनमोहन सिंह सरकार ने और बाद में मोदी सरकार ने इसके आंकड़ों को नहीं जारी करने का फैसला किया।।

क्या इस साल पड़ेगी कड़ाके की ठंड? औसत तापमान सितंबर से 2 डिग्री ज्यादा; सामने आई वेदर रिपोर्ट

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया और देश के अधिकतर हिस्सों में अक्टूबर अमेरिका ने घटाई संभावना के पहले पखवाड़े में औसत तापमान सितंबर के औसत तापमान से भी 2 डिग्री तक ज्यादा है। हल्की सर्दी की शुरुआत की बजाय गर्मी महसूस होने से आईएमडी समेत दुनियाभर की मौसम एजेंसियों की भविष्यवाणियों पर सवाल खड़े हो गए हैं।

ला-नीना परिस्थितियां पैदा होने के अनुमान से कहा गया था कि इस साल कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, लेकिन अब तक ला-नीना नहीं बन सका है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग अब भी मान रहा है कि इस बार सर्दी में सामान्य से कम तापमान रहने के आसार हैं।

नवंबर के आखिर में क्या है ला नीना की संभावना ?

ला-नीना पर अमेरिकी एजेंसी एनओएए, ऑस्ट्रेलियाई एजेंसी एबीएम से लेकर भारतीय मौसम एजेंसी आईएमडी ने अप्रैल में अनुमान लगाया था कि जून में ला-नीना विकसित होने की संभावना 85 फीसदी थी। इसके बाद मानसून निकल गया, लेकिन ला-नीना नहीं बना अब एजेंसियों का ताजा अनुमान है कि नवंबर के आखिर में ला नीना बनने की संभावना 60% है।

ऑस्ट्रेलिया वेदर ब्यूरोः इसी हफ्ते जारी बयान में कहा, आने वाले महीनों में ला नीना विकसित होने की संभावना घटती जा रही है। छह क्लाइमेट मॉडल्स में से चार ने इसकी पुष्टि की है। यह बना भी तो कमजोर होगा और कम दिनों के लिए सक्रिय रहेगा। अमेरिकी एजेंसी एनओएएः

नवंबर के आखिर में ला नीना परिस्थितियां पैदा होने की संभावना 60% है। जनवरी से मार्च तक बने रहने की संभावना 71% है। (दो महीने पहले अक्टूबर में ला-नीना विकसित होने की संभावना 75% बताई थी।) हमारा भी वही अनुमान है, जो ऑस्ट्रेलियाई ब्यूरो ने कहा है। मौसम की हर ग्लोबल एजेंसी इस वैश्विक घटना की भविष्यवाणी में फेल हुई, गहरी जांच-पड़ताल की जरूरत है।

तलाशेंगे कारण

ताकि भविष्य के पूर्वानुमान में अब गलती न हो ला-नीना या अल-नीनो जैसे अनुमान लार्ज स्केल ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल के आधार पर किए जाते हैं, जिसे भारत भी मानता है। अब डब्ल्यूएमओ में ला नीना और अल-नीनो का पूर्वानुमान लगाने वाले फोरम में चर्चा होगी कि गलत अनुमान लगने के क्या कारण रहे ताकि भविष्य के पूर्वानुमान में गलती न हो। भारत की सर्दी पश्चिमी विक्षोभों पर ज्यादा निर्भर करती है, इनका अनुमान एक से दो हफ्ते पहले ही लगा सकते हैं स्काईमेट के विज्ञानी महेश पलावत का कहना है कि सर्दी कितनी कड़ाकेदार होंगी, यह पश्चिमी विक्षोभों की संख्या और तीव्रता पर निर्भर करता है।

ला-नीना से भारत में अच्छी बारिश होती है

जिस वर्ष ये विक्षोभ अधिक आते हैं और देश के उत्तर से मध्य क्षेत्र तक उसका असर पड़ता है, उन सालों में सर्दी ज्यादा पड़ती है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में पैदा होता है और अक्टूबर से फरवरी तक उसका रास्ता हिमालय से गुजरता है। इस कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होती है और मैदानी इलाकों में बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभों का अनुमान एक से दो हफ्ते पहले ही लगा सकते हैं। ला-नीना या अल-नीनो समुद्र के दो सिरों पर तापमान के बढ़ने या घटने से पैदा होती हैं। ला-नीना से भारत में अच्छी बारिश होती है अल-नीनो में इसका उल्टा होता है।

क्या है लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम? जेल में बंद गैंगस्टर पर परिवार हर साल कितना पैसा करता है खर्च, भाई ने खोले राज

लॉरेंस बिश्नोई को लेकर उसके चचेरे भाई ने कई अहम जानकारी दी है। गैंगस्टर के भाई रमेश बिश्नोई ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई के पिता हरियाणा पुलिस में एक कांस्टेबल थे। उनके पास गांव में 110 एकड़ जमीन थी। लॉरेंस ने अपनी चाची के कहने पर नाम बदला था। चाची को लगता था कि लॉरेंस नाम उसपर अच्छा लगेगा।

नई दिल्ली। लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में बंद है, लेकिन वो अपने गैंग से लगातार संपर्क में रहता है। माना जाता है कि दुनियाभर में जहां भी भारतीय युवा हैं, वहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क है।

हाल ही में हुए एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी भी बिश्नोई गैंग ने ही ली है। इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई ने उसे लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है।

गैंगस्टर का परिवार हर साल उस पर 35 से 40 लाख रुपए खर्च करता है। 50 वर्षीय रमेश बिश्नोई ने अपने भाई जुड़ी कई चीजों की जानकारी दी है।

पिता थे हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल

रमेश बिश्नोई ने कहा कि जब लॉरेंस, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो आगे चलकर गैंगस्टर बनेगा ।गैं

लॉरेंस को हमेशा महंगे कपड़े और जूते पहने थे। आज जब वो जेल में बंद है, फिर भी उसका परिवार उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता है। द डेली गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, रमेश ने बताया कि जेल में बंद लॉरेंस का परिवार उसपर हर साल करीब 40 लाख रुपए खर्च करता है।

क्या है लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम ?

पंजाब के फिरोजपुर में जन्मे लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम बलकरन बरार है। स्कूल के दिनों से ही वो अपना नाम बदलना चाहता था। उसने अपनी चाची के कहने पर नाम बदला था। चाची को लगता था कि लॉरेंस नाम उसपर अच्छा लगेगा।

इन तीन मर्डर केस से जुड़ा है नाम

लॉरेंस बिश्नोई का नाम 3 बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर केस से जुड़ा हुआ है। साल 2022 में पंजाब के मानसा गांव में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली थी। वहीं, कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में उसका नाम सामने आया था। वहीं, हाल हीं हुए बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी भी बिश्नोई गैंग ने ली है।

साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने काले हिरण के शिकार मामले में एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है कि अगर काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान ने माफी नहीं मांगी तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।

SCENE DO NOT CROSS
CRIME SCENE DO

'सलमान का पूरा परिवार झूठा', सलीम खान के इंटरव्यू पर क्यों भड़के बिश्नोई समाज के अध्यक्ष

जयपुर। काला हिरण के शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान से बिश्नोई समाज की नाराजगी बढ़ती जा रही है। सलमान के पिता सलीम खान की ओर से दिए गए बयान के बाद बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई ने कहा कि सलमान का पूरा परिवार झूठा है। न तो हमारे समाज को और ना ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को हराम का पैसा चाहिए।

बिश्नोई समाज के खिलाफ दूसरा अपराध

सलीम खान के बयान ने समाज को पहले से अधिक आहत किया है। सलमान के परिवार द्वारा समाज के प्रति यह दूसरा अपराध है। उधर, बिश्नोई समाज के धर्मगुरु लालदास महाराज ने कहा कि लॉरेंस बच्चा है। वह धमकी नहीं दे रहा है। उसने सलमान को समाज से माफी मांगने की बात कही है। सलमान ने बिश्नोई समाज के गांव में हिरण का शिकार किया है। लॉरेंस और सलमान के बीच दुश्मनी का यही कारण है।

सलीम खान ने दिया था इंटरव्यू

दरअसल, सलीम खान ने एक साक्षात्कार में कहा है कि सलमान किस बात के लिए माफी मांगे। उसने हिरण का शिकार नहीं किया है। उसके पास कोई बंदूक नहीं थी। उसने आज तक एक कॉकरोच तक नहीं मारा है। उन्होंने सलमान को मिल रही धमकियों को फिरौती का मामला भी बताया।

...तो पुलिस, गवाह सब झूठे हैं

देवेंद्र बिश्नोई ने कहा कि सलीम खान के बयान के मुताबिक तो वन विभाग, पुलिस और चश्मदीद गवाह सब झूठे हैं। पुलिस ने हिरण का अवशेष बरामद किया था, बंदूक बरामद की गई थी। न्यायालय ने सबूत देखते हुए ही सलमान को शिकार मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी। उन्होंने कहा कि सलमान को बीकानेर में स्थित बिश्नोई समाज के प्रमुख आस्था केंद्र मुकाम में आकर माफी मांगनी चाहिए।

सलमान समाज से मांगें माफीः देवेंद्र बिश्नोई

आपको बता दें कि इससे पहले देवेंद्र बिश्नोई ने कहा था कि अभिनेता सलमान खान काला हिरण को मारने के दोषी हैं और उन्हें बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए। काला हिरण मारना अपराध है और बिश्नोई समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सलमान हमारे समाज के भी दोषी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता।

'खेत से थाली तक सब्जियों के मूल्य काअंतर करेंगे कम', कृषि मंत्री बोले- कमेटी बनाएगी केंद्र सरकार

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि सरकार खेत से लेकर थाली तक बागवानी उत्पाद (सब्जियों) की कीमतों में भारी अंतर को दूर करने के लिए समिति गठित करेगी ।राष्ट्रीय राजधानी में कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा किसान पांच रुपये में सब्जियां बेचता है तो उपभोक्ता 50 रुपये चुकाता है। इस अंतर को कम करने की जरूरत है।

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि सरकार खेत से लेकर थाली तक बागवानी उत्पाद (सब्जियों) की कीमतों में भारी अंतर को दूर करने के लिए समिति गठित करेगी ।राष्ट्रीय राजधानी में कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा, किसान पांच रुपये में सब्जियां बेचता है, तो उपभोक्ता 50 रुपये चुकाता है। इस अंतर को कम करने की जरूरत है।

अगले महीने 'कृषि चौपाल' शुरू होगी

टमाटर की कीमतों में उछाल रोकने के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया कि केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से परिवहन लागत में सब्सिडी दे सकती हैं ताकि शहरी उपभोक्ताओं को सब्जियां उचित दरों पर मिलें और किसानों के हितों की रक्षा हो सके। कृषि मंत्री चौहान ने अगले महीने 'कृषि चौपाल' शुरू करने की योजना के बारे में बताया। उन्होंने देशभर में 730 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के कामकाज को ठीक करने की आवश्यकता पर बल दिया।

कृषि भारत की आर्थिक रीढ़

उन्होंने कहा, कुछ राज्य केवीके पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं। हमें बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। उन्होंने राज्यों से कृषि में सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करने के लिए 2-2.5 एकड़ के माडल फार्म विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, कृषि भारत की आर्थिक रीढ़ है। इस क्षेत्र को मजबूत किए बिना कोई प्रगति संभव नहीं है।

रबी फसल के रिकार्ड उत्पादन पर सरकार की नजर

केंद्र सरकार को 2024-25 के रबी सीजन में रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन हासिल करने का भरोसा है। राष्ट्रीय सम्मेलन में कृषि मंत्री शिवराज ¨सह चौहान ने कहा कि भू-राजनीतिक तनाव के कारण शिपमेंट में देरी के बावजूद यूरिया और डायमोनियम फास्फेट (डीएपी) जैसे प्रमुख उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने 2024-25 रबी सीजन के लिए 164.55 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें 115 लाख टन गेहूं और 18.15 लाख टन दालें शामिल हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) के महानिदेशक हिमांशु पाठक ने कहा, जलाशयों में जल स्तर, मौसम विभाग के पूर्वानुमान और मिट्टी की नमी को देखते हुए इस वर्ष रबी सीजन में रिकार्ड उत्पादन की उम्मीद है।

चने की खेती के रकबे को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया

कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने चने की खेती के रकबे को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। कहा कि पिछले दो वर्षों में उत्पादन कम रहा है, जिसके कारण आयात की आवश्यकता पड़ी है। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और भागीरथ चौधरी के साथ छह राज्यों के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। **RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023**